वर्ष : 17 ❖ अंक : 226 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शनिवार, 25 मार्च 2023

राहुल गांधी को बड़ा झटका, लोकसभा की सदस्यता रद्द 3

ड्रग्स के लिए हमारे समुद्री मार्गों का इस्तेमान नहीं होने दे सकते : अमित शाह 8

खेल को राजनीति से रखा जाना चाहिए अलग : गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने कहा है कि खेल और राजनीति को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने आज रंगपो के पास माइन्स सिक्किम क्रिकेट ग्राउंड में एससीए ए डिवीजन पुरुष चैंपियनशिप के फाइनल मैच के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए यह मंतव्य दिया।

उनके अनुसार, राज्य में खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति की सराहना की जानी चाहिए, भले ही वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। इस संदर्भ में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां आते ही पिछली सरकार में पार्टी के सदस्य जो एससीए (सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन) के सदस्य भी थे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था या नहीं इस बारे में मैंने जानकारी ली।

राज्य में क्रिकेट के विकास के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री गोले ने कहा कि सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से राज्य के पुरुषों और महिला खिलाड़ियों को इन दिनों अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आज सिक्किम के खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है, जिससे वे भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए भी चुने जा सकते हैं। यह कहते हुए कि सिक्किम के खिलाड़ियों में भी क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत प्रतिभा है, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सिक्किम के खिलाड़ी नीली जर्सी पहनेंगे और देश के लिए खेलेंगे।

मुख्यमंत्री गोले ने राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को धन्यवाद दिया है।

इसके अलावा, उन्होंने सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन की बीसीसीआई से संबद्धता के लिए संघर्ष को भी याद किया, जब वह इसके अध्यक्ष थे तब मतदान के अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। उधर, आज एक बार फिर मुख्यमंत्री गोले ने राज्य में एक और क्रिकेट मैदान बनाने का मुद्दा उठाया।

सिक्किम बनेगा देश का पहला टीबी मुक्त राज्य : राज्यपाल

राज्यपाल आचार्य ने 10 टीबी रोगियों को लिया गोद

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 10 टीबी रोगियों को गोद लिया और 1 लाख 20 हजार का चेक जिला क्षय रोग अधिकारी (गंगटोक जिला) अरुणा प्रधान को निक्षय मित्र के तहत सिक्किम को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प से सहयोग राशि के रूप में सौंपा।

विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आज राजभवन के सभाकक्ष में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी सम्मलेनऑनलाइन प्रसारण में भाग लिया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मनसुख मडविया, यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पर निदान, प्रभावी उपचार को समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बीमारी से निपटने के लिए अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सचिव राजभवन, जिला टीबी अधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी, राजभवन के परिजन व एसटीएनएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी ऑनलाइन प्रसारण में भाग लिया। इसी मौके पर टीबी को हराने के संकल्प की प्रतिबद्धता को संकल्प प्रदान करते हुए राजभवन की कर्मचारी संगीता राई ने हम होंगे कामयाब गाना गाकर सबका दिल जीता।

आज के कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय ने उपस्थित सभी को क्षय रोग उन्मूलन में अपनी सहभागिता प्रदान करने और सिक्किम को भारत गणराज्य का पहला क्षय मुक्त राज्य बनाने में अपने सहयोग देने की शपथ दिलाई। अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम सरकार भारत सरकार के साथ सिक्किम राज्य पूर्ण रूप से टीबी मुक्त होने की दिशा में दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि टीबी मुक्त राज्य के प्रति सिक्किम के लोगों

के सामूहिक दृढ़ संकल्प के साथ सिक्किम टीबी को खत्म करने की दिशा में बहुत आगे आ गया है और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सिक्किम निश्चित रूप से देश के पहले टीबी मुक्त राज्य के रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि उठिए और उठाइए, जागिए और जगाइए और संकल्प लीजिए कि जब भारत सरकार का अगला कार्यक्रम होगा तब हमारा राज्य उस दिशा में ताली बजाने वाला राज्य नहीं बल्कि ताली बजवाने वाला राज्य होगा। हारेगा टीबी, जीतेगा भारत, जीतेगा सिक्किम। भारत सरकार ने टीबी से निपटने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित कई पहल की हैं, जिसका उद्देश्य सभी रोगियों को मुफ्त और व्यापक टीबी देखभाल प्रदान करना है।

किसानों के बीच रेनबो ट्राउट मछली के चारे वितरित

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 24 मार्च । प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना के तहत आज जिले के अपर श्रीबादाम में डीसी भीम ठटाल और राज्य मत्स्य निदेशालय द्वारा किसानों और अन्य लोगों में रेनबो ट्राउट मछली के चारे वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में राज्य मत्स्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक लोबजांग लामा, सहायक मत्स्य निदेशक योवा राज शर्मा, ट्राउट मछली पालन सहकारी समिति अध्यक्ष काल बहादुर गुरूंग, उपाध्यक्ष सामदुप भूटिया, प्रबंधक कृष्ण कुमार गुरुंग, मछली किसान उत्पादक संगठन सीईओ अर्पण गुरूंग के साथ विभागीय के फील्ड अधिकारी, कर्मचारी एवं अपर श्रीबादाम के 30 से अधिक मछली पालक किसान भी मौजूद थे।

इस दौरान डीसी ने श्रीबादाम के लाइव फिश वेंडिंग सेंटर और काल बहादुर के ट्राउट हैचरी हाउस का दौरा कर कहा कि एक आकांक्षी

जिले के रूप में सोरेंग ने स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि एवं जल संसाधन सहित पांच तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें मत्स्य पालन के तीन तत्व भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने गांवों में मत्स्य निदेशालय की गतिविधियों के तेज प्रसार हेतु निदेशालय को विशेष रूप से कक्षा 9-12 कक्षा के स्कूली छात्रों और एसएमसी सदस्यों के साथ शिक्षकों, कर्मचारियों को योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।

वहीं संयुक्त मत्स्य निदेशक ने अपर श्रीबादाम के 60 फीसदी से अधिक निवासियों के आजीविका हेतु रेनबो ट्राउट फार्मिंग में शामिल होने की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में 15 लाभार्थियों में रेनबो ट्राउट मछलियों के 2000 चारे वितरित किए गए, जिनकी कीमत 20 रुपये प्रति है। इसके साथ ही निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि जम्मू व कश्मीर के बाद सिक्किम भारत में रेनबो ट्राउट मछली पालन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। कार्यक्रम में मत्स्य रेंज अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा ने सजावटी मछलियों, विभिन्न प्रकार के एक्वेरियम, और इनके माध्यम से आजीविका और रोजगार पैदा करने पर प्रस्तुति दी।

कृषि क्षेत्र सिक्किम के विकास की कुंजी : मंत्री शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग मंत्री के श्री लोक नाथ शर्मा की अध्यक्षता में आज प्रदेश में 'किसान मेला' आयोजित करने के लिए बैठक हुई। कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों के सचिव जेडी भूटिया, एसके तमांग और डॉ. पी सेंथिल कुमार ने क्रमश: अपने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

मंत्री शर्मा ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य के विकास और प्रगति की कुंजी हैं और इन क्षेत्रों की ताकत का प्रदर्शन करके व्यावसायिक क्षमता का दोहन करने का समय आ गया है। इसलिए

उन्होंने एक कृषि मेला प्रस्तावित किया जहां कृषि, बागवानी और पशुपालन के सभी हितधारक जैसे कि किसान/उत्पादक, प्रोसेसर, विपणक आदि मिलते हैं और व्यापार के अवसरों का पता लगाते हैं।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों के साथ-साथ उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

यह कार्यक्रम तीन दिनों के लिए सरमसा गार्डन में आयोजित किया जाएगा, जो नवंबर के महीने में संभावित रूप से निर्धारित है। इसके लिए तीन विभागों के सचिवों की एक संचालन समिति का गठन किया जाना है। यह समिति एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी और धन के विभिन्न स्रोतों का भी पता लगाएगी।

शिक्षा मंत्री ने लिंके स्कूल के नए भवन का किया उद्घाटन

अनुगामिनी नि.सं.

पाकिम, 24 मार्च । सिक्किम के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने आज लिंके गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में चार कमरों वाले नये भवन का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य शिक्षा अधिकारी एडी छेत्री, एसएमसी सलाहकार कमल काफ्ले, सेवानिवृत्त डीआईजी छिरिंग भूटिया, पाकिम जेडी, एसडीएम मुख्यालय, पारखा बीडीओ और इंजीनियरिंग शिक्षा सेल के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंत्री लेप्चा ने राज्य शिक्षा विभाग के कई पहलों पर प्रकाश डालते हुए विद्या प्रवेश और निपुण भारत सहित सभी सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी प्रोत्साहनों और अनुदानों का लाभ उठाने पर भी जोर दिया। वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग सेल को पुराने स्कूल भवन को तोड़कर नया निर्माण करने का भी निर्देश दिया।

इस दौरान सीईओ एडी छेत्री ने निपुण भारत, विद्या प्रवेश, समग्र शिक्षा और अन्य शैक्षणिक प्रयासों में स्कूल की भागीदारी की प्रशंसा की। वहीं एसएमसी सलाहकार काफ्ले (सेवानिवृत्त विशेष सचिव) ने स्कूली बच्चों के लिए नए स्कूल भवन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग नृत्य भी प्रस्तुत किया गया।

सिक्किम नेपाली संस्कृति परिषद के सदस्यों ने राज्यपाल से की मुलाकात

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से आज अशोक चौरसिया के नेतृत्व में सिक्किम नेपाली संस्कृति परिषद ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की।

इस भेंट के दौरान राज्यपाल ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषा और साहित्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सिक्किम नेपाली संस्कृति परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा की भाषा, भेष-भूषा भोजन, भ्रमण और भवन

हम सबको जोड़ता है और यह जोड़ने का प्रवाह सदा ही बना रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वैभवशाली भारत की पहचान ही अनेकता में एकता है। जिसका सिक्किम जीवंत उदारहण है और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है।

राज्यपाल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषा और साहित्य के संरक्षण के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

मैराथन मैन अमर सुब्बा बने गेजिंग जिले के तपेदिक एम्बेसडर

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 24 मार्च । विश्व तपेदिक दिवस के उपलक्ष्य पर आज गेजिंग सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य विभाग की तपेदिक इकाई और हेल्प ब्रदर्स ताशीडिंग एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के पशुपालन व पशु चिकित्सा सलाहकार दुर्गा प्रसाद प्रधान मुख्य अतिथि थे।

उनके अलावा कार्यक्रम में राज्य सरकार के धार्मिक विभागीय सलाहकार आरएस भूटिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर खेमराज भट्टाराई, डॉ. भूषण शर्मा, जिला तपेदिक अधिकारी डॉ. स्मृति राई, सिक्किम मैराथन मैन अमर सुब्बा, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि डॉ. डीके गुरुंग, गेजिंग नगर पंचायत के एमईओ गोपाल शर्मा एवं विभिन्न कॉलेजों के छात्र, स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारी व अन्य मौजूद थे।

इस दौरान सिक्किम के मैराथन मैन अमर सुब्बा को गेजिंग जिले के तपेदिक एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में जिला अस्पताल की तपेदिक अधिकारी डॉ. स्मृति राई ने इस बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में इसका नि:शुल्क उपचार किये जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि बीमारी की पहचान के बाद सरकार की ओर से मरीज को पौष्टिक भोजन हेतु हर महीने 1000 रुपए दिये जाते हैं। साथ ही उन्होंने तपेदिक को हर जिले, राज्य और देश से समूल समाप्त करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सिक्किम को 2025 तक तपेदिक मुक्त करने के (शेष पृष्ठ ०३ पर)

नए एसटीएनएम अस्पताल में कटे हेंठ और तालु के मरीजों के लिए सर्जिकल कैम्प का उद्घाटन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, एनएचएम के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्थानीय एसटीएनएम मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा कोलगेट द्वारा प्रायोजित मिशन स्माइल के सहयोग से आज नए एसटीएनएम अस्पताल में कटे होंठ और तालु के मरीजों के लिए सर्जिकल कैम्प का उद्घाटन हुआ।

इस अवसर पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव छेवांग ग्याछो भूटिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ कार्यक्रम में विभाग के प्रधान निदेशक डॉ. येली डी. चान्कापा, डॉ. टेकेंद्र राई एवं डॉ. पेमा सेडेन लेप्चा के अलावा एसटीएनएम के चिकित्सा अधीक्षक केबी गुरूंग, मिशन स्माइल सीईओ कॉनराड गॉडफ्रे डेनिस और सर्जिकल टीम लीडर कर्नल डॉ. विजय लैंगर एवं अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि शिविर 28

मार्च तक चलने वाले इस कैम्प के दौरान मरीजों की जांच और ऑपरेशन किया जाएगा। पूरे कैम्प में तीस से अधिक रोगियों का दो चरणों में ऑपरेशन किया जाएगा। पहले चरण में कटे होंठ और दूसरे चरण में कटे तालु का ऑपरेशन किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल मार्च में भी ऐसा कैम्प सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, जिसमें 52 रोगियों की जांच करने के बाद 32 की सर्जरी हुई थी। कैम्प में शामिल हुई चिकित्सा टीम में भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली, फिलीपींस और सिंगापुर के सर्जन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, तकनीशियन, नर्स और एसटीएनएम अस्पताल के कर्मचारी शामिल हैं।

कार्यक्रम में वक्तव्य रखते हुए एचएफडब्ल्यू सचिव भूटिया ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) की पहल पर स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सकारात्मक बदलावों की सराहना करते हुए इससे रोगियों के जीवन में आये परिवर्तन को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने रोगियों एवं उनके अभिभावकों को कैम्प का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया और कैम्प (शेष पृष्ठ ०३ पर)

वर्तमान सरकार ने हमारी पहचान को किया है कमजोर : चामलिंग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । एसडीएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने कल दरामदिन के लोगों से मुलाकात की। यह जानकारी खुद पवन चामलिंग ने दी।

उन्होंने बताया कि वहां के लोगों ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति और इसके प्रति अपने असंतोष पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एसडीएफ सरकार के सत्ता से बाहर होने से जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकर दुख हुआ कि सोम्बारिया बाजार भी पहले की तरह चहल-पहल वाला नहीं रहा और लोगों की क्रय शक्ति गंभीर रूप से कम हो गई है। बाजारों में कारोबार चौपट हो गया है।

चामलिंग ने दावा किया कि वहां के व्यापारियों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी भावी पीढ़ी के लिए गलत का विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लोग पूरी तरह से भय में जी रहे हैं।

चामलिंग ने कहा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सिक्किम के लोगों ने परिवर्तन के लिए सरकार बदली थी, लेकिन दुर्भाग्य से, हमने जो देखा है वह बदतर के लिए परिवर्तन है न कि बेहतर के लिए। इस बार सिक्किम के लोगों को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक होना होगा और सही सरकार का चयन करना होगा जो सिक्किम के भविष्य के लिए चिंतित हो।

पूर्व मुख्यमंत्री चामलिंग ने

कहा कि एसडीएफ सरकार ने 25 साल के शासन में बहुत काम किया है, लेकिन इसे सही मायने में समझने और सराहने के लिए लोगों को शोध करना होगा और जो काम किया गया है, उसकी गहराई का खुद पता लगाना होगा। वर्तमान सरकार ने हमारी पहचान को कमजोर कर दिया है और केवल एसडीएफ ही सिक्किम और सिक्किमी लोगों की विशिष्ट पहचान और अस्तित्व की रक्षा कर सकता है।

प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि विदेश मंत्रालय (एमईए) सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।

जवाब में कहा गया है, सरकार प्रवास से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सचेत है। इस दिशा में, विदेश मंत्रालय सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद प्रवासन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।

ड्राफ्ट बिल विदेशों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यबल को सशक्त बनाने के अलावा प्रवासन चक्र के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा। यह एक सक्षम संस्थागत ढांचे को स्थापित करता है, जो उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित है।

मंत्री ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों और भारत के विकास में उनके योगदान को पहचानने और सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

2020-2023 से मदद और ई-माइग्रेट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 26,730 शिकायतें, जिनमें मुआवजे, मजदूरी की चोरी और अवशिष्ट भुगतान से संबंधित मामले शामिल हैं, पिछले तीन सालों के दौरान मदद पोर्टल पर भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज किए गए थे।

इस अवधि के दौरान, 29,640 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें पिछले सालों में पंजीकृत शिकायतों में से कुछ शामिल हैं।

जहां भी आवश्यक हो, ऐसे मामलों को तुरंत मिशनों और पोस्ट द्वारा संबंधित कंपनियों के साथ मुद्दों को हल करने के लिए उठाया गया।

भारतीय मिशनों और पोस्टों ने भी भारतीय मजदूरों और उनके नियोक्ताओं के बीच हर संभव सहायता प्रदान करके मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा की। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान इन मुद्दों को मेजबान देशों की सरकारों के साथ भी उठाया गया था और इस प्रक्रिया के माध्यम से कई मामलों को सुलझाया गया है।

जवाब में कहा गया कि इसके अलावा, कुछ देशों ने प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सहायता उपाय भी शुरू किए हैं।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एम.के.नागपाल ने आदेश सुनाने की तिथि 31 मार्च निर्धारित की है।

अदालत ने सोमवार को आप नेता को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

21 मार्च को, न्यायाधीश नागपाल ने जांच एजेंसी से लिखित सबमिशन और प्रासंगिक निर्णय दर्ज करने के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के एक वकील ने कहा था कि सीबीआई द्वारा कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, जो निरंतर हिरासत की आवश्यकता होगी।

वकील ने कहा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि सिसोदिया गवाहों को धमका रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं। हर बार जब उन्हें सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वह पेश हुए।

वकील ने कहा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को धमकाने आदि का कोई वास्तविक सबूत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सिसोदिया को जमानत दें।

सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने कहा था: केवल मोबाइल फोन ही नहीं, फाइलें भी नष्ट हो गईं। मैं बहुत गंभीर हूं कि सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर अभ्यास था।

सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इससे समझौता होगा और जांच प्रभावित होगी।

सिसोदिया ने मंगलवार को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही एक अदालत में जमानत याचिका भी दायर की थी।

कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी किया था।

सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।

देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत : केजरीवाल

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल खुलकर उनके साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश में वन पार्टी, वन सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। इसे तानाशाही कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। यह देश बचाने की लड़ाई है और इसके लिए सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा के परिसर में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह एक निर्णय के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, यह चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि इस देश की आजादी के लिए पूरे देश ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इस देश और उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल का यह रुख महत्त्वपूर्ण है। अब तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चे में शामिल होने से कतराती रही थी। लेकिन राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद से ही वे खुलकर कांग्रेस के साथ खड़े होते देखे जा रहे हैं। अदालत का निर्णय आने के बाद भी उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया था। राहुल प्रकरण पर जिस तरह ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने राहुल के पक्ष में बयानबाजी की है, माना जा रहा है कि यह विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकता है।

विजेंद्र गुप्ता की विधानसभा सदस्यता बरकरार, हाईकोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली विधानसभा से निलंबन रद्द कर दिया है। अब वे सोमवार से दुबारा विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। 21 मार्च को उन्हें सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने के आरोप में सदन से निलंबित कर दिया गया था। भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल सरकार की तानाशाही पर न्याय की जीत बताया है।

दिल्ली का बजट पेश किए जाने के पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हुई तकरार में बजट के कुछ बिंदुओं के लीक होने का मामला गरमाया था। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जब दिल्ली का बजट पेश कर रहे थे, तब भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट के प्रमुख बिंदुओं के लीक होने का मामला सदन में उठाया था और इस पर सरकार से सफाई की मांग की थी। उनके द्वारा यह मुद्दा बार-बार उठाने के कारण उन्हें एक साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था।

विजेंद्र गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में न्याय की जीत हुई है। अरविंद केजरील सरकार अपने विरुद्ध बोलने वाले जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर कर उनकी आवाज चुप कराना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उचित पाया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली की जनता के हक में अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

यूपी के 6 विधायकों को अदालतों द्वारा दोषी ठहराए

लखनऊ, 24 मार्च (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के छह विधायकों को पिछले पांच वर्षों में विभिन्न आरोपों में अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान को पिछले महीने मुरादाबाद की एक अदालत के आदेश के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्यता का सामना करना पड़ा था, उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। वह रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे।

उन्हें 29 जनवरी, 2008 को राज्य राजमार्ग पर धरना देने का दोषी पाया गया, वह धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ शिविर पर हमले के मद्देनजर उनके काफिले को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक दिया था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके पिता के साथ यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

संयोग से यह दूसरी बार है जब स्वार विधानसभा सीट पर काबिज अब्दुल्ला आजम को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जाली जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें पहले 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

नवंबर 2022 में, भाजपा विधायक विक्रम सैनी को उनकी खतौली सीट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उन्हें मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2013 के दंगों से जुड़े एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। अयोध्या में गोसाईंगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को 2021 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब अयोध्या में एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें और दो अन्य को 1992 में मार्कशीट की जालसाजी का दोषी पाया था। उन्हें जुर्माने के साथ पांच साल की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट ने तीनों को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दोषी ठहराया था।

एक अन्य भाजपा विधायक अशोक चंदेल की सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 साल पहले हमीरपुर में हुई सामूहिक हत्या के लिए दोषी ठहराया था। अशोक चंदेल के खिलाफ मामला 26 जनवरी, 1997 का है जब स्थानीय भाजपा नेता राजीव शुक्ला और चंदेल के बीच एक मामूली विवाद के कारण गोलीबारी हुई, जिसमें शुक्ला के दो बड़े भाई राकेश, राजेश और भतीजे अंबुज, वेद नायक और श्रीकांत पांडे सहित पांच लोग मारे गए।

गोलीबारी में दो बच्चों सहित पांच और लोगों को गोली लगी थी, जिसके बाद चंदेल और नौ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी 10 आरोपियों को 15 जुलाई, 2002 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर ने इस आधार पर बरी कर दिया था कि गवाहों की गवाही संदिग्ध थी। इस फैसले को राजीव शुक्ला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने फैसले को पलट दिया।

हमीरपुर से चार बार के विधायक और पूर्व सांसद अशोक चंदेल अब आगरा जेल में बंद हैं। उन्नाव में बांगरमऊ सीट से विधायक रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को 2020 में बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जून 2017 में उन्नाव के माखी गांव में नाबालिग से बलात्कार में कथित संलिप्तता को लेकर हुए हंगामे के बाद चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।

अप्रैल 2018 में पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने के बाद मामला सुर्खियों में आया, पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों बाद उसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई।

प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता अपराध: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ एक गतिविधि माना जाना तय है। शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की वैधता की पुष्टि की है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं होता है।

जस्टिस शाह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद भी उसकी सदस्यता जारी रखता है तो वह सजा का भागी होगा।

न्यायमूर्ति शाह ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए यूएपीए की धारा 10 (ए) (आई) को बरकरार रखा, जो एक ऐसे संघ की सदस्यता बनाता है, जिसे गैरकानूनी घोषित किया गया है।

दो दिवसीय 'बॉर्डर एरिया प्रोग्राम' सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनईजेडसीसी) दीमापुर द्वारा 23-24 मार्च को पांगथांग स्थित सिक्किम सशस्त्र पुलिस कैम्प और लिंगदम रांका स्थित भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस कैम्प में दो दिवसीय 'बॉर्डर एरिया प्रोग्राम' आयोजित किया। पांगथांग में इसके शुरुआती दिन राज्य के संस्कृति सचिव बसंत कुमार लामा मुख्य अतिथि थे।

उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि बसंत लामा ने कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के सुंदर लोक नृत्यों को प्रस्तुत करने में कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान के शानदार अवसर के लिए सांस्कृतिक केंद्र को धन्यवाद दिया।

वहीं लिंगदम रांका में आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट अमूल्य राय, अतिरिक्त संस्कृति निदेशक श्रीमती सोनम वांगमू शेंगा एवं संस्कृति विभाग के ओएसडी के अलावा आमलोगों और आईटीबीपी कर्मियों तथा उनके परिजनों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। केंद्र की ओर ने बताया गया कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जम्मू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम और सिक्किम के स्थानीय दलों के 110 कलाकारों ने भाग लिया। इन मंडलियों ने महाराष्ट्र का कोली लोकनृत्य, जम्मू का जागरण नृत्य, नागालैंड का अफिलो कुवो लोकनृत्य, असम का दोमाही किकोन और महाराष्ट्र का बधाई प्रस्तुत किया। वहीं सिक्किम के स्थानीय लोक नर्तकों ने भूटिया, लेप्चा और नेपाली समुदायों के अपने समृद्ध लोक गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए।

मुझे नहीं लगता देश का '12वीं पास' कोई पीएम हुआ, सातवें आसमान पर है उनका अहंकार : केजरीवाल

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल बोले कि उपराज्यपाल जब यह बोल रहे थे कि मेरी सरकार पारदर्शी है सरकार ने सारे क्षेत्र में बेहतर काम किया तो हमारा सीना चौड़ा हो रहा था। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हम आपको और मौके देंगे यदि आप हमारे कामों में टांग न अड़ाये। हम काम करना चाहते हैं रोज-रोज की परेशानी नहीं चाहते। हमारे शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें यह जज्बा विदेश में मिली ट्रेनिंग से आया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोगों ने क्या हाल बना दिया है देश का। अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। केजरीवाल ने बिना किसी का नाम लिए '12वीं पास' प्रधानमंत्री कहकर तंज कसा। बोले, 'भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है, सबसे कम पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री कोई हुआ है, मैं नहीं समझता कोई '12वीं पास' प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका सातवें आसमान पर है। सुबह से शाम तक किसको जेल भेजें, किसकी सदस्यता रद्द करें, बस यही चलता रहता है'।

एलजी पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल बोले उपराज्यपाल द्वारा अड़चन लगाए जाने के बाद भी दिल्ली के विकास में हमने बहुत काम किया। दिल्ली में जो भी अच्छी पॉलिसी बन रही हैं उसके लिए रिसर्च का काम डीडीसीडी कर रहा हैं। एलजी ने एसडीएम के दफ्तर को बंद करवा दिया। महीने से ऑफिस बंद है। दिसंबर और मार्च में कुछ और टीचर्स को जाना था उन शिक्षकों की फाइल को एलजी ने रोक दी, इससे किसी को फायदा नहीं हुआ।

केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने 17000 लोगों की योग कक्षाओं को बंद करवा दिया। एलजी दिल्ली में बिजली की सब्सिडी बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसे बंद नहीं होने दूंगा, एलजी ने मेयर के चुनाव नहीं होने दिया। कोर्ट के आदेश पर मेयर का चुनाव हुआ और हम जीत गए। दिल्ली के बजट को रोक दिया बाद में उसी बजट को पास करना पड़ा। एलजी ने पिछले आठ साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले डबल इंजन की बात करते हैं। दिल्ली में जब एलजी और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेगी तो यह डबल इंजन की सरकार होगी। आप के विधायक के पास पुलिस वाले आ कर बोलते हैं कि आप को जेल भेज देंगे। जो जेल में जाने से डरता हैं तो पार्टी को छोड़ दो। पार्टी में रहोगे तो जेल जाना पड़ सकता हैं। केजरीवाल बोले कि पार्टी का जो विधायक जेल गया उसके घर को हम चलाएंगे। अच्छा वकील देंगे। मनीष सिसोदिया भगत सिंह के चेले हैं। वह नहीं डरे।

केजरीवाल बोले कि भाजपा के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं वे भाजपा के साथ रहें और जो देश को बचाना चाहते हैं आज भाजपा छोड़ दो।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 608
नामांकन सूचना सं. 71/2023

एम्स, पीजीआईएमईआर, एनआईएमएचएएनएस, एससीटीआईएमएसटी एवं जेआईपीएमईआर के लिए जुलाई- 2023 सत्र के लिए डीएम/एम.सीएच एवं एमडी (अस्पताल प्रशासन) पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आईएनआई-एसएस प्रवेश परीक्षा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, **एम्स नई दिल्ली एवं 6 अन्य एम्स, पीजीआईएमईआर, एमआईएमएचएएनएस, जेआईपीएमईआर एवं एससीटीआईएमएसटी** में **जुलाई, 2023** के लिए पोस्ट डॉक्टोरल **(डीएम/एम.सीएच. (3 वर्ष)/एमडी (अस्पताल प्रशासन) पाठ्यक्रम** में नामांकन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण

पाठ्यक्रम	संस्थानें	खुलेगा	बंद होगा
डीएम/एम.सीएच. (3 वर्ष)/एवं एमडी (अस्पताल प्रशासन)	एम्स- नई दिल्ली एवं 6 एम्स, पीजीआईएमईआर, एनआईएमएचएएनएस, जेआईपीएमईआर एवं एससीटीआईएमएसटी	23.03.2023	06.04.2023 को 5:00 बजे

आवश्यक: नियमावली पुस्तिका, विस्तृत सूचना आदि के लिए कृपया वेबसाइट **www.aiimsexams.ac.in** देखें। सभी आगामी संशोधन/अतिरिक्त जानकारी/नवीनतम सूचना केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा अत: तब तक सभी आवेदनकर्ताओं को नियमित रूप मे वेबसाइट देखते रहने की आवश्यकता है।

सहायक नियंत्रक (परीक्षा)

CBC 17112/12/0043/2223

विपक्ष के विरोध के बीच वित्त विधेयक लोकसभा में पारित

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। लोकसभा ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा के वॉयस वोट से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक पैनल का गठन किया जाएगा।

वित्त विधेयक में कम से कम 75 संशोधन हैं, जिनमें से सभी को वॉयस वोट से अनुमोदित किया गया, यहां तक कि कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अडाणी मामले में जेपीसी जांच की मांग की।

विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और 'राहुल गांधी को सदन में बोलने दें' और 'हम अंग्रेजों से लड़े, हम मोदी और आरएसएस से लड़ेंगे' की तख्तियां दिखाईं।

इस बीच, बिल पर बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि पेंशन के मुद्दे और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने को लेकर वित्त सचिव के अधीन एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि दृष्टिकोण को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

सीतारमण ने आगे कहा, 'यह कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश यात्राओं के लिए पेमेंट्स लिब्रालाइस्ड रेमिटेंस स्किम (एलआरएस) के तहत नहीं लिया जा रहा है और वे स्रोत पर टैक्स कलेक्शन से बच जाते हैं। विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाने और उस पर टैक्स कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से गौर करने का अनुरोध किया जा रहा है।'

वित्त विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, निचले सदन को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्यों को अपनी तख्तियों को फाड़ते और अध्यक्ष की कुर्सी पर फेंकते देखा जा सकता है।

वित्त विधेयक 2023, 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।

राहुल गांधी को बड़ा झटका, लोकसभा की सदस्यता रद्द

राजेश अलख

नई दिल्ली, 24 मार्च । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। 'मोदी सरनेम' मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया। राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है और अब उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, और कम से कम दो साल कैद की सजा सुनाई जाती है, वह संसद की सदस्यता ले लिए अयोग्य हो जाता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर विशेष रूप से चुनाव की घोषणा करता है।

इससे पहले 10 जुलाई, 2013 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में ये फैसला सुनाया था कि कोई भी संसद सदस्य (सांसद), विधानसभा सदस्य (विधायक) या एक विधान परिषद (एमएलसी) का सदस्य जो एक अपराध का दोषी है और न्यूनतम दो साल की कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?

इसी मामले को लेकर बीजेपी विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था और गुरुवार को इस मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया।

हालांकि उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है लेकिन अदालत के फैसले की वजह से उनकी संसद सदस्यता पर 'स्वत: अयोग्य' हो गई।

राहुल को अयोग्य ठहराना लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' : कांग्रेस

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को उन्हें चुप करने की साजिश करार दिया है।

कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' है और वह मोदी सरकार के इस सुनियोजित कदम के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी।

पार्टी ने यह भी कहा भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम पांच बजे पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं को बताया, आज शाम पांच बजे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति तय की जाएगी।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा डर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से लगता है। लोकतंत्र की हत्या करने लिए उन्होंने गांधी की संसद सदस्यता रद्द की है। वे सच बोलने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं।

खड़गे ने कहा, देशवासी यह तानाशाही नहीं सहेंगे। लोकतंत्र की हिफ़ाज़त के लिए हम जेल तक जाएंगे। हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जाना ताबूत में आखिरी कील है। यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। यह मोदी सरकार का सुनियोजित कदम है ताकि संसद में राहुल गांधी की आवाज को बंद कर दिया जाए। हम इससे कानूनी और राजनीतिक रूप से निपटेंगे। सच की जीत होगी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। हम धमकी के आगे नहीं झुकेंगे और खामोश नहीं होंगे। प्रधानमंत्री से जुड़े अडाणी महाघोटाले में जेपीसी बनाने के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, नीरव मोदी घोटाला- 14,000 करोड़ रुपया, ललित मोदी घोटाला- 425 करोड़ रुपया, मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 करोड़ रुपया। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्योंभाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं।

उन्होंने सवाल किया, क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, जैसी भाजपा, संघ, नरेन्द्र मोदी जी से उम्मीद थी कि मोदी अडाणी संबंधों पर वे राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देंगे, वही हुआ। राहुल गांधी के चार साल पुराने बयान पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलने दोगे तो जनता की अदालत में जाएंगे।

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।

यूपी में 2.70 लाख टीबी मरीजों को लिया गया गोद, 70 प्रतिशत हुए रोगमुक्त : योगी

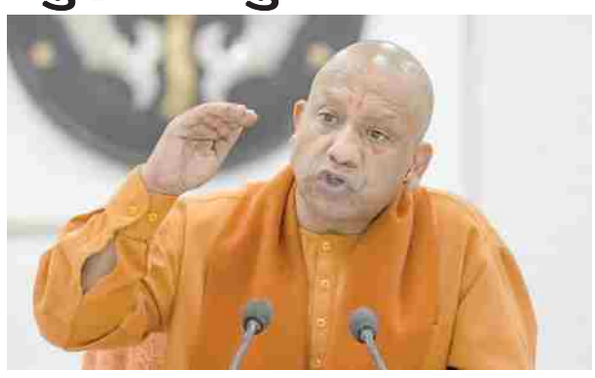

वाराणसी, 24 मार्च (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में 2 लाख 70 हजार टीबी मरीजों को सरकारी स्तर पर गोद लेने का काम हुआ है, जिसमें से 70 प्रतिशत मरीज आज रोगमुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मौजूदगी में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' में बोल रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के टीबी रोगियों को पोषण सहायता के लिए प्रदेश सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से अबतक 422 करोड़ का भुगतान किया गया है। हम यूपी की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में समर्थ बनकर उभरा है। 2.70 लाख टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। 70 प्रतिशत रोगमुक्त भी हुए हैं।

तीन दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन काशी में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने कहा, स्टॉप टीबी कैंपेन की अधिशासी निदेशक डॉ लुशिका के उद्बोधन में ये सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत हुई हैं। भारत अपने अमृत काल के प्रथम वर्ष में है, ऐसे में पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत को जी-20 का नेतृत्व हासिल हुआ है। देश 2025 तक प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य यूपी में कभी देश के 21 फीसदी टीबी रोगी पाए जाते थे। विगत पांच वर्ष में यूपी में 16 लाख 90 हजार टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से 422 करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

योगी ने कहा, पीएम आयुष्मान वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों में 80 हजार से अधिक किट युद्धस्तर पर वितरित करने की कार्रवाई चल रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में प्रत्येक योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया है जो यूपी के 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने के लिए के उद्देश्य से किया गया है। खासतौर पर संचारी रोग, जापानी और एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम को यूपी में 96 प्रतिशत तक समाप्त करने में सफलता हासिल की गई है।

अयोग्यता पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- सिर्फ राष्ट्रपति के पास है पावर

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता पर सवाल उठाया और कहा कि केवल राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्तियां हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत के संविधान के तहत सिर्फ राष्ट्रपति के पास किसी सांसद को अयोग्य ठहराने का अधिकार है।

सीओआई के तहत एक सांसद को अयोग्य घोषित करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं- अनुच्छेद 103 यदि अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत अयोग्यता होती है।

लोकसभा से अयोग्य होने के बाद, चुनावी राजनीति में राहुल गांधी का भाग्य अब केवल उस कानूनी राहत पर निर्भर करता है जो उन्हें अदालतों से मिल सकती है क्योंकि चुनाव आयोग उनकी सीट को खाली घोषित कर सकता है और चुनावों की घोषणा कर सकता है।

कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि दोषसिद्धि ही अयोग्यता को गतिमान कर देती है।

पूर्व सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मजीद मेमन ने कहा, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अदालत में अपील के बाद राहुल की सजा निलंबित कर दी जाती है, तो लोकसभा से उनकी अयोग्यता को टाला जा सकता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि '23 मार्च को फैसला और 24 मार्च को अयोग्यता। जिस गति से व्यवस्था चलती है वह आश्चर्यजनक है। प्रतिबिंब, समझने या कानूनी समीक्षा के लिए समय की अनुमति देने पर कोई समय बर्बाद नहीं होता है, जाहिर है, भाजपा पार्टी या सरकार में संयम की कोई आवाज नहीं है, शुद्ध परिणाम यह है कि संसदीय लोकतंत्र को एक और क्रूर झटका लगा है।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महा मेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

लोकसभा सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। यह आदेश शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया और इस पर लोकसभा के महासचिव ने हस्ताक्षर किए।

मैराथन मैन अमर ....

लिए इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है।

वहीं धार्मिक विभाग के सलाहकार आरएस भूटिया ने तपेदिक के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु इस तरह के कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हुए इस तरह के मुद्दों को घर-घर में जागरूकता लाने को जरूरी बताया। कार्यक्रम को डॉ. भूषण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर खेमराज भट्टाराई सहित अन्य ने भी संबोधित किया।

इस दौरान 10 किमी ओपन मैराथन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसके पुरुष वर्ग में विकास भुजेल और महिला वर्ग में प्रति राई विजयी हुई। उन्हें 10-10 हजार नकद राशि के साथ पदक से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे मोहित सुब्बा एवं फुर्वा तमांग को 5-5 हजार रुपए एवं तीसरे स्थान पर रहे पासंग वांगेल एवं रिया तमांग को 3-3 हजार रुपए के साथ पदक प्रदान किये गये। इनके अलावा निंग्मा लादेन शेर्पा और बिनीता चौथे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में राज्य और इसके बाहर के 120 से अधिक प्रतियोगितयों ने भाग लिया था।

नए एसटीएनएम अस्पताल .....

के लिए आई टीम को धन्यवाद देते हुए इसको सफल बनाने हेतु विभाग द्वारा हरसम्भव सहयोग का आश्वासन दिया।

वहीं अपने मुख्य भाषण में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. चोडेन नोर्बू ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) को धन्यवाद देते हुए शिविर को सफल बनाने हेतु शामिल होने वाले राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय डॉक्टरों की टीम का स्वागत किया। इसके साथ ही मिशन स्माइल के सीईओ कोनराड गॉडफ्रे डेनिस ने मिशन स्माइल के बारे में बताते हुए कहा कि 2002 से काम कर रहा मिशन कुल 131 मिशन चला रहा है और पूरे देश में 43 हजार मुस्कान फैला रहा है।

विपक्ष एकजुट समर्थन पर बोले राहुल, 'मैं हर कीमत चुकाने को तैयार'

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर एक ओर जहां राहुल गांधी ने कहा वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। वहीं सभी विपक्षी दल उनके समर्थन में उतर आए हैं। अब तक दूरी बनाई हुई टीएमसी प्रमुख ने भी उनका पक्ष लिया।

लोकसभा से अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।

वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता! जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है।

सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, यह निंदनीय है कि भाजपा अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए आपराधिक मानहानि के रास्ते का उपयोग कर रही है, जैसा कि अब राहुल गांधी के साथ किया गया है। यह विपक्ष के खिलाफ ईडी/सीबीआई के घोर दुरूपयोग के शीर्ष पर आता है। ऐसे सत्तावादी हमलों का विरोध करें और उन्हें हराएं।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। 'चोर को चोर कहना' हमारे देश में अपराध हो गया है। चोर-लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई है। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। यह तानाशाही के अंत की शुरूआत है। अब लड़ाई को उचित दिशा देनी होगी।

वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने ट्वीट कर कहा, लेटेस्ट मेडिकल अपडेट. लोकतंत्र को मृत घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा और कुछ नहीं हो सकता। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, इसके पीछे आधारहीन तथ्य हैं, तर्क हैं। सभी दलों को अब मिलकर इस तानाशाही को जमींदोज करना होगा। अन्यथा आजदी के 75 वें वर्ष पर जो देश का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कभी संभव नहीं हो पाएगी।

वहीं आरजेडी ने औपचारिक ट्विटर से अकाउंट से कहा, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष के नेता समझ लें अब लड़ाई का तरीका क्या होने जा रहा है, इस तानाशाही कदम ने उसी की तस्दीक की है! सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से भारतीय लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज!

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी. बहुत डरपोक निकले! भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और कम पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री - उनसे सरकार चलती नहीं है और अहंकार उनका सातवें आसमान पर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि राहुल पहले ऐसे नेता नहीं हैं, जिनकी सदस्यता चली गई। इसके पहले भी कई ऐसे सांसद और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट ने दो साल या इससे अधिक की सजा सुनाई है। इस तरह के मामलों में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक रहे विक्रम सैनी, लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल भी इसका उदाहरण थे लेकिन केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

दरअसल राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया और अब उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR HOOGHLY MORNING
FRIDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:121 DrawDate on:24/03/23
1st Prize ₹1 Crore/- 50E 77189
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 77189 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
00530 01039 11128 12894 20885 26664 48928 52330 54679 59070
3rd Prize ₹450/-
1058 1110 1317 1845 2579 3268 4853 5708 8317 9118
4th Prize ₹250/-
2505 3809 4505 4771 5406 6129 7288 7322 7341 8008
5th Prize ₹120/-
0003 0018 0032 0062 0172 0209 0313 0403 0518 0548
0551 0796 0973 1090 1353 1427 1469 1516 1805 1937
2298 2314 2488 2510 2682 2783 2837 2854 2892 3202
3224 3396 3437 3455 3486 3502 3532 3607 3612 3640
3831 3938 3946 3950 4233 4386 4504 4516 4662 4795
4819 4908 4979 5001 5042 5093 5104 5107 5120 5196
5212 5294 5419 5465 5489 5672 5931 5967 6073 6247
6265 6340 6623 6885 6954 7040 7321 7615 7628 7668
8031 8095 8097 8153 8494 8505 8609 8620 8893 9189
9204 9335 9377 9387 9408 9409 9512 9655 9713 9823
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR EARTH FRIDAY
WEEKLY LOTTERY
Draw No:121 DrawDate on:24/03/23
1st Prize ₹1 Crore/- 98B 68943
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 68943 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
12310 26052 29081 43774 46146 52491 67811 77317 81876 96760
3rd Prize ₹450/-
1415 2018 4103 4334 5651 5709 6466 6815 7665 8504
4th Prize ₹250/-
1200 2230 2542 5417 6473 6513 7476 7626 8133 8926
5th Prize ₹120/-
0062 0317 0530 0612 0625 0626 0703 0726 0903 0939
1019 1338 1400 1452 1454 1470 1720 1958 1970 2047
2091 2192 2210 2250 2355 2489 2515 2602 2709 2817
2876 2938 3047 3112 3148 3160 3243 3299 3380 3489
3755 3779 3810 4008 4493 4523 4534 4615 4778 4784
4897 4916 5093 5142 5260 5272 5439 5462 5538 5561
5732 5845 5888 5900 5909 5952 6019 6058 6306 6418
6559 6687 6786 6805 6834 7012 7051 7123 7232 7252
7424 7615 7941 8003 8090 8117 8200 8462 8465 8505
8556 8571 9040 9084 9350 9551 9798 9833 9970 9972
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR VULTURE EVENING
FRIDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:221 DrawDate on:24/03/23
1st Prize ₹1 Crore/- 89H 75892
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 75892 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
21288 22864 36073 38346 43711 52861 60292 87221 93153 98758
3rd Prize ₹450/-
1627 2768 3606 3822 4508 4879 5848 5850 8731 9532
4th Prize ₹250/-
0097 0589 1830 1860 2253 2975 3173 3358 9100 9243
5th Prize ₹120/-
0217 0356 0578 0590 0726 1064 1075 1151 1169 1374
1400 1494 1551 1707 1722 1803 1977 2009 2052 2076
2106 2231 2240 2296 2318 2346 2540 2708 2916 3095
3224 3254 3268 3706 3870 4080 4399 4480 4564 4630
4657 4676 4774 4912 5021 5023 5059 5150 5198 5221
5222 5562 5717 5802 6247 6265 6291 6487 6510 6580
6626 6785 7103 7155 7246 7249 7302 7444 7504 7643
7688 7803 8054 8092 8291 8399 8459 8475 8500 8624
8740 8743 8803 8930 9022 9137 9236 9285 9367 9374
9405 9455 9499 9597 9683 9713 9726 9761 9912 9941
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

जरा संभलकर बोलिए

सूरत की एक अदालत की ओर से आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। चूंकि उनकी सजा निलंबित करके उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने की सुविधा दी गई है, इसलिए उन्हें फौरी राहत मिल गई है, लेकिन यदि उच्चतर न्यायपालिका की ओर से उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाती तो उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है।

पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अपनी सजा पर राहुल गांधी के यह कहने का कोई मतलब नहीं कि सत्य मेरा भगवान है। महात्मा गांधी के इस कथन का उल्लेख करना इसलिए व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें जिस बयान के लिए मानहानि का दोषी पाया गया, उसका सत्य से कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने के लिए ललित मोदी, नीरव मोदी का उल्लेख करते हुए यह जो कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, वह हर दृष्टि से एक अपमानजनक और अभद्र बयान था।

पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर उनकी ओर से दिया गया यह बयान एक जाति विशेष के लोगों के प्रति उनकी दुर्भावना का परिचायक था। यही कारण रहा कि उन्हें मानहानि का दोषी पाया गया। राहुल गांधी को यह आभास होना चाहिए था कि वह अपने बयान से एक जाति के लोगों को लांछित कर रहे थे। वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि संभलकर बोलना छोड़ दें और जो मन में आए, बोल दें। समस्या यह है कि वह ऐसा ही करते रहते हैं और इसी कारण रह-रहकर आलोचना और विवाद का केंद्र बनते रहते हैं।

किसी को कुछ भी कह देना और यहां तक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना गैर जिम्मेदाराना हरकत ही नहीं, स्वयं को अति विशिष्ट समझने की मानसिकता भी है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी सामंती मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। होना तो यह चाहिए था कि राहुल गांधी अपने अपमानजक बयान के लिए क्षमा याचना कर लेते, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया। परिणाम यह है कि अब उनकी राजनीति पर ही बन आई है। वह जिस कठिनाई में फंसे हैं, उसके लिए अपने अतिरिक्त अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते।

यह विचित्र है कि कांग्रेसजन राहुल गांधी का बचाव करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। किसी को राजनीति करने के नाम पर कुछ भी कहने की छूट नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी तो इससे और अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को गलत तरीके से उल्लेख करते हुए जब उन्होंने यह कह दिया था कि अब तो शीर्ष अदालत भी कह रही है कि चौकीदार चोर है, तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी।

दोराहे पर विपक्ष और चौराहे पर विपक्षी एकता

नीरजा चौधरी

गुरुवार को जब मैं यह आलेख लिख रही हूं कि कैसे 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद मजबूत होते दिख रहे राहुल गांधी को कुछ विपक्षी दल संदेह से देख रहे हैं, नेहरू-गांधी परिवार के इस महत्वपूर्ण सदस्य को 2019 के उनके 'मोदी' सरनेम को 'चोर' से जोड़ने वाले बयान से संबंधित एक आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। मैं इस पर बाद में आऊंगी।

भारतीय राजनीति का यह विरोधाभास है कि मजबूत राहुल भाजपा के लिए अच्छी खबर है और विपक्ष के लिए खराब खबर। अच्छी खबर इसलिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के 'मोदी बनाम राहुल' बनने की संभावना है और आज जैसे हालात हैं, उसमें लगता है कि इससे मोदी को लाभ होगा। पूरे देश में 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा ने राहुल का कद बढ़ाया है और यह उनकी अपनी उपलब्धि है, जिसमें परिवार के नाम का कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए उन्हें मोदी के मुख्य विरोधी की तरह देखा जाने लगा और वह विपक्ष का 'चेहरा' बनते भी दिखे, फिर चाहे विपक्षी दल उन्हें इस रूप में स्वीकार करें या न करें।

विपक्ष की ओर से नेता कौन होगा, इसका फैसला तो 2024 के चुनावों के बाद ही होगा और यह स्थिति भी तब आएगी, जब विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हो, पर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। लिहाजा, मोदी बनाम विपक्ष से कौन? यह बहस भाजपा के कथानक को मदद करती है, न कि विपक्ष के एजेंडा को।

आज विपक्ष दो खेमों में बंटा हुआ है और उनके मतभेद इस मुद्दे के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जिनका अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और वे कांग्रेस को नेतृत्व की भूमिका देने पर राजी हो सकती हैं। इनमें द्रमुक (तमिलनाडु), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झारखंड), राजद और जनता दल (यू) (बिहार), एनसीपी और शिव सेना (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

हाल ही में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली लेफ्ट पार्टियां गैर-भाजपा गठबंधन का समर्थन करेंगी, फिर कांग्रेस उसका नेतृत्व करे या न करे। इन दलों के अलावा ऐसी पार्टियां और नेता भी हैं, जो अपनी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं हैं, जिनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल), अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (दिल्ली और पंजाब), के चंद्रशेखर राव की बीआरएस (तेलंगाना) शामिल हैंऔर ये कांग्रेस (राहुल) का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 2024 में गांधी-नेहरू परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये वे सीटें हैं, जहां सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर अतीत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चुनाव जीतने में मदद की है।

पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने गौतम अदाणी की प्रधानमंत्री मोदी से कथित करीबी की जेपीसी जांच की कांग्रेस की मांग से प्रत्यक्ष रूप से खुद को दूर रखा था। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति, जो कि कांग्रेस की 'बड़े भाई' की भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, कुछ अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़ी हैं। ये पार्टियां जानती हैं कि कांग्रेस के पुनर्जीवन की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा यह सिर्फ अहंकार का मामला नहीं है, यह संकट इन क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है।

विपक्ष में गतिरोध टूटने का एक ही तरीका हो सकता है कि राहुल पीछे हट जाएं और विपक्षी एकता का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना कठिन। यह कांग्रेस के नए जुड़े समर्थकों को हताश करने जैसा होगा, जिन्होंने भले ही अभी यह तय न किया हो कि वे किसे वोट देंगे, लेकिन राहुल को नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं।

क्षेत्रीय दल अभी अपनी स्थिति को तौल ही रहे थे कि राहुल को दोषी ठहराने वाला फैसला आ गया। सूरत की अदालत के राहुल को दोषी ठहराने वाले फैसले के कुछ मिनट बाद ही राहुल के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जताया, जबकि उन्हें विपक्ष की किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर देखा जाता है। यह अतीत से आगे बढ़ने का भी संकेत है; जबकि दिल्ली और पंजाब में आप को सफलता मिली ही कांग्रेस की कीमत पर है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जब शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तब कांग्रेस उनके बचाव में सामने नहीं आई थी। अपने दो लेफ्टिनेंट-सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में होने और केंद्र तथा उपराज्यपाल के साथ हर कदम पर टकराव होने के कारण केजरीवाल अलग-थलग पड़ गए हैं। यहां तक कि उनके लिए दिल्ली का बजट पारित करवाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में उन्हें लग रहा हो कि विपक्षी दलों को निशाना बनाने में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है।

अभी यह सवाल अहम है कि क्या राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। आपराधिक मामलों में सजा सुनाए जाने पर सदन की सदस्यता जा सकती है और छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसा कि लालू प्रसाद यादव के मामले में हो चुका है। गुजरात की निचली अदालत ने राहुल को गुजरात उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए तीस दिनों का समय दिया है। लेकिन क्या उच्च न्यायालय फैसले पर स्थगन दिए बिना मामले की सुनवाई कर सकता है? दूसरे शब्दों में, राहुल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, भले ही वह उनके मामले की सुनवाई करता रहे?

राजनीतिक मोर्चे पर अभी क्या कुछ होगा, नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या इससे राहुल गांधी के प्रति जनता में सहानुभूति पैदा हो सकती है-भले ही भाजपा इस मुद्दे को हवा दे रही हो? क्या राहुल 'पीड़ित' के रूप में क्षेत्रीय दलों की एकता में उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं?

विपक्षी दल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की भर्त्सना कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके मतभेद भी कायम हैं। हालांकि उनके भीतर से यह स्वर भी उठ रहे हैं कि जब भाजपा के दूसरे कार्यकाल में उन्हें मुकदमों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर मोदी के तीसरे कार्यकाल में क्या होगा? क्या राहुल की दोषसिद्धि विपक्षी राजनीति में निर्णायक बिंदु बन सकती है? या इसका फायदा भाजपा को होता रहेगा?

बदलता कारोबारी माहौल और विदेशी निवेश की संभावनाएं

अवधेश कुमार

पिछले दिनों श्रीनगर के सेमपोरा में विदेशी निवेश से निर्मित होने वाले 250 करोड़ रुपये की लागत के एक मॉल की आधारशिला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी। यह श्रीनगर ही नहीं, विदेशी पूंजी से बनने वाला प्रदेश का पहला मॉल होगा, जिसे 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दुबई का एम्मार समूह इसका निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में डेढ़ सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत वाले एक-एक आईटी टावर का विनिर्माण भी एम्मार समूह कर रहा है।

यह इसका प्रमाण है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की बदली परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर में भी विदेशी निवेश आ रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीनों में 5,000 से अधिक देसी व विदेशी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

यह सच है कि वहां नए उद्योग आरंभ हो रहे हैं। यह प्रदेश के बदलते आर्थिक, वित्तीय व कारोबारी स्थिति का ही प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं की कुल लागत 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। प्रदेश ने अगले कुछ वर्षों में कुल 75,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। वस्तुत: जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार पूर्व की सभी सरकारों से अलग दृष्टिकोण से काम कर रही है। आर्थिक गतिविधियों द्वारा प्रदेश का माहौल बदलना इनमें प्रमुख है।

हाल ही में इंडिया-यूएई इन्वेस्टर्स मीट में जम्मू कश्मीर की ओर से उपराज्यपाल सिन्हा ने घोषणा की कि निवेश संबंधी प्रस्ताव आने के 15 दिन के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी घोषणा शायद ही हुई हो। भले ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं, पर शांति और बेहतर सुरक्षा माहौल को कोई नकार नहीं सकता। आम लोग यह महसूस करने लगे हैं कि पहले की तरह आतंकवादियों के पनपने, उन्हें संरक्षण मिलने तथा हिंसात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। पिछले वर्ष एक करोड़ 88 लाख पर्यटकों के आने की सूचना है।

अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ऐसे अनेक कानूनों का अंत कर दिया गया, जो वहां की स्वाभाविक, आर्थिक व कारोबारी गतिविधियों के रास्ते की बाधाएं थीं। अगर भूमि कानून नहीं बदला होता, तो उपराज्यपाल यह वादा नहीं कर सकते थे कि निवेश घोषणा के 15 दिनों के अंदर जमीन उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि शत-प्रतिशत आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। मगर तीन वर्षों में निवेश के लिए वातावरण तैयार करने में काफी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। सामान्य एवं प्रोफेशनल शिक्षा का भी विस्तार हुआ है।

अभी तक कृषि और पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मूलाधार रहा है। लेकिन अब कंपनियां पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, रसद, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी रुचि दिखा रही हैं और निवेश कर रही हैं। स्वाभाविक ही आधारभूत संरचना एवं सरकारी नीतियों का ध्यान इन्हीं पर होगा।

भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज बदलाव का परिदृश्य उत्पन्न कर रहा है। एक लाख करोड़ रुपये की तो हाईवे और उससे जुड़ी अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। रेल मार्ग के जरिये कश्मीर को इसी वर्ष कन्याकुमारी से जोड़ने पर तेजी से काम चल रहा है। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हुआ है। इन सबसे निवेशकों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है। सरकार के साथ उद्योगपतियों, कारोबारियों का भी दायित्व है कि वे वातावरण बदलने में अपने सक्रिय भूमिका के साथ सहयोग करें।

जनवरी, 2021 में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने नए निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी, जिसका सकारात्मक असर हुआ। उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर भी अन्य राज्यों के समानांतर आर्थिक विकास की पटरी पर दौड़ता दिखाई देगा।

किसान आंदोलन की दस्तक

आदित्य चोपड़ा

राजधानी दिल्ली में महापंचायत करके किसानों ने पुन: आन्दोलन की चेतावनी दे दी है। इसका प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि उनके साथ सरकार ने जो वादे किये थे, वे पूरे नहीं किये गये हैं और सैकड़ों किसानों पर विभिन्न राज्यों में मुकदमें चल रहे हैं। ये मुकदमें गत आन्दोलन में शामिल किसानों के हैं। इसके साथ ही उनकी ऊपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का ऐसा फार्मूला भी अभी तक नहीं निकला है जिससे उन्हें लागत की डेढ़ गुनी कीमत मिल सके। किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरे में लाया जाये। यहां सबसे बड़ा मूलभूत प्रश्न यह है कि किसान अपनी फसल बेचने के बाद स्वयं उपभोक्ता बन जाता है। खास कर छोटे किसानों को तो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए उन्हीं कृषि ऊपजों तक को बाजार से खरीदना पड़ता है जिनका वह उत्पादन करते हैं। केन्द्र सरकार जब पिछले वर्षों में तीन नये कृषि कानून लाई थी तो वे कृषि उत्पाद विपणन प्रणाली से सम्बन्धित थे। इनका किसानों ने पुरजोर विरोध किया जिसकी वजह से ये कानून वापस लेने पड़े परन्तु हम देख रहे हैं कि केवल भूमि पर उत्पादन करने वाले किसानों की ऊपज के खुदरा दामों में ही वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि दर्ज हो रही है। इसके बावजूद किसान उचित लाभकारी मूल्यों की मांग कर रहे हैं।

इसकी वजह यह है कि कृषि उपयोग में आने वाले जरूरी सामान के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से किसान का लागत मूल्य भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि दुधारू पशुओं के चारे के दामों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है जिसकी वजह से दूध के बढे. हुए दामों के बावजूद पशु पालक किसानों के मुनाफे की दर कम हो रही है। इसके साथ ही देश की कुल 130 करोड़ जनसंख्या में 81 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी पांच हजार रुपए महीने से कम है। इन्हें सरकार हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। इसका मतलब यह निकलता है कि यदि भारत में प्रत्येक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या पांच मानी जाये तो देश के कुल 26 करोड़ परिवारों में से 16 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राप्त पांच किलो अनाज पर जीवन गुजर-बसर करना पड़ रहा है। इनमें निश्चित रूप से भूमिहीन किसान-मजदूरों के परिवारों की संख्या सर्वाधिक होगी उसके बाद छोटा-मोटा काम-धंधा या प्राइवेट नौकरी करने वाले परिवार होंगे।

अत: सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि जीवनोपयोगी अनाज व अन्य जरूरी खाद्य सामग्री के दाम बाजार में इस तरह नियन्त्रित रखे जायें जिससे गरीब कहे जाने वाले परिवार अपने भरण- पोषण की सामग्री अपनी जेब के मुताबिक खरीद सकें। इसके लिए जरूरी होगा कि कृषि उत्पादन की लागत कम से कम रखी जाये जिससे जरूरी चीजों के दाम आसमान न छू सकें। क्योंकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जो कायदे-कानून होते हैं उनके अनुसार किसान कभी भी अपनी उपज का वह मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते जिससे उनकी आमदनी डेढ़ गुनी हो जाये। इसकी वजह यह है कि किसानों की उपज मौसम के लिहाज से बाजार में इकट्ठा आती है और मंडियां उपज से लबालब भर जाती हैं जबकि बाजार मांग व आपूर्ति (डिमांड एंड सप्लाई) के सिद्धान्त पर वस्तुओं की कीमत तय करता है। जब बाजर में सप्लाई बढ़ती है तो उपज के दाम घट जाते हैं और किसान को अपना माल उन्हीं दामों पर बेचना पड़ता है क्योंकि उसे रोकड़ा की जरूरत होती है। उसकी सारी उम्मीदें ऊपज या फसल बेच कर प्राप्त होने वाले धन पर ही लगी रहती हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इन परिस्थियों में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है?

एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के जुड़ जाने से इस पर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते कृषि सब्सिडी कम से कम करने का दबाव रहता है और दूसरी तरफ देश की गरीब आबादी को उसकी जेब के मुताबिक खाद्यान्न सुलभ कराने की जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए जरूरी है कि कृषि उपयोगी कच्चे सामान की कीमतें कम से कम रखी जायें और किसानों को खाद से लेकर बिजली आदि सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाये। हाल ही में महाराष्ट्र के ख्रयाज उत्पादक किसानों ने नासिक से मुम्बई तक पैदल मार्च करके राज्य सरकार के सामने अपनी जायज मांगें रखी थीं। इन पैदल मार्च करने वाले किसानों में अधिसंख्य आदिवासी किसान थे जिनकी जंगलों की जमीन के पट्टे तक उनके नाम नहीं हैं और उनके पास खेती करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

इस राज्य की बड़ी-बड़ी ख्रयाज मंडियों में ख्रयाज दो रुपए किलो तक के हिसाब से खरीदी जा रही थी। ऐसे विरोधाभास पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के किसानों में हमें देखने को मिलेंगे। इनका कोई न कोई हल तो हमें निकालना ही होगा। और यह हल हमें देश के अभी तक के सबसे बड़े किसान नेता स्व. चौधरी चरण सिंह के फार्मूले से ही निकालना होगा। उस फार्मूले का पुन: अध्ययन करने व उस पर मनन करने का समय आ चुका है। चौधरी साहब कहा करते थे कि यदि किसान की आमदनी बढेगी तो देश की आमदनी ही नहीं बल्कि इसका चहुंमुखी विकास भी होगा। यह काम गांवों व कस्बों में कृषि मूलक कुटीर उद्योग लगाने से ही होगा। किसानों की महापंचायत कह रही है कि राज्यवार आन्दोलन चलाया जायेगा।

पंजाब की चुनौती

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह सही प्रश्न पूछा कि आखिर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का सरगना अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर भाग कैसे गया? हाई कोर्ट ने इस पर भी अपनी नाखुशी प्रकट की कि जब अमृतपाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था तो फिर समय रहते उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भले ही पंजाब पुलिस कह रही है कि वह जल्द ही भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तीन दिन बीत गए हैं और वह खाली हाथ है। पुलिस को न केवल अमृतपाल तक पहुंचना होगा, बल्कि उसके समर्थकों तक भी। संभव है कि वह पुलिस से बचने में इसीलिए समर्थ हो, क्योंकि उसे छिपाने वाले सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में ऐसे तत्वों की संख्या इसीलिए बढ़ी है, क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वह पिछले करीब छह माह से कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने के साथ युवाओं को उकसाने और वैमनस्य पैदा करने में लगा हुआ था।

समझना कठिन है कि उसे यह सब करने की छूट कैसे मिली हुई थी और वह भी तब, जब वह हथियार और हिंसा की बात कर रहा था? उसने हथियारबंद लोग भी एकत्रित कर लिए थे और उन्हीं के बल पर वह एक थाने में धावा बोलने में समर्थ रहा। कायदे से इस घटना के बाद ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें देरी की गई? इस देरी के दुष्परिणाम से बचना है तो अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द करनी होगी। इसके साथ ही उसके समर्थकों पर भी निगाह रखनी होगी और उन तत्वों पर भी, जो माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे ही तत्वों के कारण पंजाब के कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना पड़ा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मानें तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर माहौल खराब करने वालों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी उनकी चुनौती खत्म नहीं हुई है। पहली चुनौती तो फरार अमृतपाल को पकड़ना है और दूसरी, अन्य अतिवादी एवं अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाना। यह इसलिए आसान नहीं, क्योंकि पंजाब में कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह ऐसे हैं, जो दबे-छिपे स्वर में अमृतपाल जैसे तत्वों के पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे तत्व अमृतपाल की निंदा करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि पंजाब से अधिक खालिस्तान समर्थक देश से बाहर और विशेष रूप से कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में नजर आ रहे हैं, इसलिए पंजाब सरकार के साथ भारत सरकार को भी सतर्क रहना होगा। ये खालिस्तान समर्थक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार में जुट गए हैं। उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि वे भारतीय राजनयिक केंद्रों को भी निशाना बना रहे हैं।

गुजिया कीट- इस कीट का प्रकोप फरवरी से मई-जून माह तक अधिक होता है. यह कीट पौधे की कोमल टहनियों व फूलों के डंठलों से चिपके रहते हैं और उनका रस चूसते है.

आम के कीट-रोग

गूदे को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं जिस कारण फल सड़ने लगते हैं व पकने से पूर्व जमीन पर गिर जाता है. जो कि खाने योग्य नहीं रहता है.

प्रबंधन- फल मक्खी कीट से प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट करें व फल मक्खी की संख्या जानने एवं उसके नियंत्रण हेतु यौन गंध ट्रेप (मिथाईल यूजिनॉल 0.1 प्रतिशत एवं मैलाथियान 0.1 प्रतिशत का घोल) लगाना चाहिए. यदि यौन गंध ट्रेप में फल मक्खियों की संख्या बढ़ती हुई पायी जाए तो हर सप्ताह में ट्रेप के द्रव्य को बदल देना चाहिए.10 यौन ग्रंथ ट्रेप प्रति हैक्टेयर क्षेत्र के लिये पर्याप्त होते हैं. कीट के प्रकोप की अवस्था में डाइमिथियेट 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घुलकर या कार्बोरिल 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें.

छाल खाने वाला कीट

प्रारंभ में यह कीट छाल को खरोंचकर खाती है तथा बाद में तने शाखाओं विशेषकर उनके जोड़ वाले स्थानों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है. यह कीट रात्रि के समय अधिक सक्रिय रहता है.

प्रबंधन- कीट द्वारा प्रभावित तनों, शाखाओं से जाल को अलग कर नष्ट कर देना चाहिए. सुरंगों में नुकीले तार को डालकर सुंड़ियों को मार देना चाहिए तथा सुरंगों में पेट्रोल या नुवान में रूई को भिगोकर भर दें तथा छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें.

खर्रा दहिया

इस रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों बौर तथा नए फलों पर पाये जाते हैं. इस रोग का विशेष लक्षण सफेद कवक या चूर्ण के रूप में प्रकट होता है. इस रोग का प्रकोप छोटे-छोटे फलों पर भी होता है जिस कारण यह फल सूखकर गिर जाते हैं. इस रोग द्वारा आम के उत्पादन 7 में लगभग 15 से 20 फीसदी की हानि होती है.

प्रबंधन - इस रोग के प्रबंधन के लिये आम में बौर निकलने से पूर्व 0.5 ग्राम सल्फर को प्रति लीटर पानी या 0.5 मिलीलीटर हैक्साकोनाजोल को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें.

कोयलिया रोग- इस रोग के प्रकोप के कारण फल का निचला सिरा मुलायम पड़कर काला पड़ जाता है. तथा बाद में शक्त पड़ जाता है. यह रोग ईंट के भट्टे से निकले धुएं के कारण होता है. इस बीमारी का प्रकोप भुट्टे से 630 मीटर की दूरी तक देखा जाता है.

प्रबंधन- आम के बागों को ईंट के भट्टे से कम से कम 16 किलोमीटर की दूरी छोड़कर लगाना चाहिए या भट्टे की चिमनी को जमीन से 15 मीटर ऊपर उठाकर लगाना चाहिए.

रोग

कालवर्ण- यह रोग पौधों की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों के कोमल भाग पर प्रकोप करके उनको सुखाने में मदद करता है. इस रोग के कारण फलों पर काले धब्बे पड़ जाते है.

प्रबंधन- इस रोग के प्रबंधन के लिये कॉपर आक्सीक्लोराइड 2 मिलीग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर या बोर्डो मिश्रण (3-3-50) का छिड़काव करें.

प्रबंधन- मई, जून के दिनों में पेड़ के चारों तरफ गुड़ाई करके मैलाथियान कीटनाशक भुरकाव करें. इस कीट के बचाव हेतु पेड़ के तने को चारों ओर 400 गेज की पालीथिन की पट्टी को जमीन से एक फुट की ऊंचाई पर लपेटकर सुतली से इसे बांध दें तथा निचले सिरे पर ग्रीस लगा दें. यदि इस कीट के शिशु पेड़ों पर चढ़ चुके हैं. डायमिथियेट 1 मिली लीटर की मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें.

भुनगा- यह आम का सबसे हानि पहुंचाने वाला कीट है. इस कीट के शिशु व वयस्क दोनों ही पौधे के मुलायम प्ररोहों, पत्तियों तथा फूलों का रस चूसते हैं. जिसका फूलों पर अधिक प्रभाव पड़ता है. यह कीट एक प्रकार का मीठा रस छोड़ता है जिस पर काली फफूंदी उगती है. जो पत्तियों पर काली परत जमाकर पेड़ों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है.

प्रबंधन- इस कीट के प्रबंधन हेतु सायपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर या इमिडा - क्लोप्रिड 1.5 मिलीलीटर या रोगोर 1.0 मिली लीटर की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें.

फल मक्खी

फल मक्खी कीट फल की परिपक्वता से पूर्व फलों की त्वचा के अंदर अंडे देकर क्षति पहुंचाती है. जिनमें से मैगेट निकलकर परिपक्व फलों के

तना बेधक कीट-

यह कीट तने के अंदर प्रवेश करके सुरंग बनाता है. इसके द्वारा बनाये गये छेद से लकड़ी का बुरादा, कीट की विष्ठा आदि बाहर निकलता रहता है.

प्रबंधन- प्रकाश प्रपंच के माध्यम से कीटों को आकर्षित करके नष्ट करें.कीट द्वारा ग्रसित पौधे के भाग को काटकर नष्ट कर दें. कीट द्वारा बनाये गये छेद से अंदर सल्फास की आधी गोली या मिट्टी के तेल को पिचकारी के माध्यम से अंदर डालकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें.

बंचीटाप या गुम्मा रोग

बागवानों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधियों में गुम्मा विकार का प्रमुख स्थान है. इससे टहनियों पर निकलने वाली पत्तियां तथा शाखाएं छोटी होकर गुच्छा बना लेती है और इनकी वृद्धि रुक जाती है. इसे वानस्पतिक गुच्छा कहते हैं.

इसी प्रकार बौर का भी गुच्छा बन जाता है. बाद में कभी-कभी इन गुच्छों में से छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल आती है इन गुच्छों में फल नहीं आते हैं.

प्रबंधन-

इस रोग से प्रभावित भागों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए तथा नेप्थलिन एसिटिक एसिड 200 पी.पी.एम.(2 मिली ग्राम प्रति लीटर पानी) का घोल बनाकर छिड़काव करें.

डेयरी व्यवसाय में दुधारू मादा पशुओं से उचित उत्पाद प्राप्त होने पर इस व्यवसाय में सफलता मिलती है. पशुधन सुधार हेतु आज देश में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. पशुपालक प्रमुख तीन बातों का ध्यान रखें उन्नतीशील प्रजनन, पशुधन के लिए पर्याप्त संतुलित आहार की व्यवस्था एवं पशुओं का रखरखाव व संक्रमण रोगों से बचाव.

दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराएं

पशु प्रजनक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. वर्तमान में देशी अवर्गीकृत पशुओं में उन्नतिकरण के लिए संकर प्रजनक की नीति काम में ली जा रही है, इस हेतु निम्न गुणवत्ता वाले देशी मादा पशुओं को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी/देशी सांड से प्राकृतिक तरीके से या उनके हीमकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराकर 50 प्रतिशत विदेशी खून वाले संकर पशु प्राप्त किये जाते हैं. ये संकर पशु शुद्ध विदेशी पशुओं की तुलना में हमारे यहां की जलवायु में अधिक उपयुक्त होते हैं. यहां पर उच्च गुणवत्ता वाले सांड से मतलब है जिसकी मां या दादी ज्यादा दूध देती है. इस तरह के सांडों की संख्या भी बहुत कम होती है, अत-कम संख्या में मिलने वाले सांडों का अधिकतम उपयोग करना अति आवश्यक है, कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त बछड़े-बछड़ी ही भविष्य में अच्छे सांड एवं अच्छी दुधारू गाय बनेंगी.

कृत्रिम गर्भाधान क्या है

कृत्रिम विधि द्वारा सांड का वीर्य एकत्र करके मादा जननांग की तीव्र या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर स्वच्छतापूर्वक वीर्य को स्थापित करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है.

कृत्रिम गर्भाधान के उद्देश्य :- शीघ्रता से पशुओं का नस्ल सुधार करना, पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाले सांड से अधिक संख्या में बछड़े-बछड़ियां पैदा करना.

कृत्रिम गर्भाधान से लाभ

- उन्नतशील बछड़े-बछड़ियां कृत्रिम से ही संभव है.
- नस्ल सुधार करने हेतु सांडों का अधिकतम उपयोग कृत्रिम गर्भाधान से ही हो सकता है.
- पशुपालकों को कम शुल्क में उत्तम प्रजनन सुविधा कृत्रिम गर्भाधान से ही हो सकता है.
- प्रजनन संबंधी संक्रामक रोग जैसे - ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनिअसिस, विब्रिओसिस आदि से पशु को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बचाया जा सकता है.
- कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दूर स्थित ग्रामों भी उत्तम नस्ल के सांड द्वारा प्रजनन संभव है.
- कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों मादा गर्भित कराई जा सकती है.
- कृत्रिम गर्भाधान में उत्तम किस्म के सांडों का वीर्य प्रयोग होता है.
- कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बहुत छोटी या अपंग मादा को भी गर्भित किया जा सकता है.
- विभिन्न जातियों के पशुओं से नई-नई जातियां उत्पन्न करना संभव है.
- मादा पशु के ताव में आने पर पशु पालक को सांड के लिए जगह-जगह घूमने की आवश्यकता नहीं होती है.
- इस विधि द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है. कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रत्येक पशु का विस्तृत अभिलेख रखना संभव है, जिससे प्रजनन संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकती है- इस विधि में सांड वीर्य से कई गायें गर्भित की जा सकती हैं.

डेयरी मादा पशु के ताव/गर्मी में आने के लक्षण

- पशु का बेचैन होना, अकारण रम्भाना, चंचल प्रतीत होना एवं व्यर्थ इधर-उधर भागना.
- बाह्य योनी में सूजन तथा योनी द्वार से चिकना एवं पारदर्शी स्राव निकलना.
- दूसरे पशु के जननांगों को सूंघना.
- पशु द्वारा अचानक दाना, चारा एवं पानी बंद या कम कर देना.

- पशु द्वारा बार-बार रूक-रूककर पेशाब करना, पूंछ को थोड़ा ऊपर उठाते हुए योनी फलकों पर एक तरफ मोड़ते हुए टिका देना.

पशुपालकों के ध्यान योग्य बातें

- गाय या भैंस 21 दिन पश्चात् ताव/पाली में आती हैं. 4 ताव/गर्मी में आने के 16 घंटे के भीतर इन्हें गर्भित कराने हेतु पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए.
- सामान्यत- गाय 9 माह 9 दिन तथा भैंस 10 माह 10 दिन में ब्याती है.
- ब्याने के तीन माह पश्चात् गाय-भैंस को पुन- गर्भित हो जाना चाहिए.4गर्भित करवाने के तीन माह बाद उसका गर्भ परीक्षण पशु चिकित्सक से अवश्य करा लेना चाहिए.

नोएडा में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर का वीडियो वायरल, रिश्वत को लेकर ठेकेदार कर रहा है झगड़ा !

नॉएडा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नॉएडा के सेक्टर-16 स्थित कार्यालय के मुख्य अभियंता पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो में एक ठेकेदार घूस देने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिलने की बात कह रहा है। जिससे नाराज़ हो कर मुख्य अभियंता ठेकेदार को कार्यालय से बाहर निकलवा देते हैं। जानकारी के अनुसार, सेक्टर-66 मामूरा गांव में आशुतोष चौहान ने ई-वाहन चार्जिंग प्वाइंट के लिए एलएमवी-11 में निवेश मित्र पर 55 केवीए के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन 25 जनवरी को किया गया था। आशुतोष का कार्य निगम के ठेकेदार दया शंकर तिवारी कर रहे हैं। तिवारी ने बताया कि बिजली की लाइन और ट्रांसफार्मर लगाने का काम निगम की टीम के सुपरविजन में किया गया है। इसके लिए 15 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क भी दिया गया। निगम में करीब सवा लाख रुपये जमा भी किए गए हैं, लेकिन प्रकिया पूरी करने के बाद भी निगम कनेक्शन स्वीकृत नहीं कर रहा है। दया शंकर ने बताया कि 55 केवीए के कनेक्शन की स्वीकृति के लिए वो 16 मार्च से मुख्य अभियंता के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो कनेक्शन स्वीकार नहीं किया जा रहा था लेकिन कुछ समय बाद स्वीकृति के लिए 25 हजार रुपये की मांग रखी गई। इस पर दया शंकर ने 12 हजार रुपये जमा करा दिए।

दया शंकर ने बताया कि उन्हें बिजली दफ्तर में कहा गया कि तीन सौ रुपये प्रति केवीए के हिसाब से उन्हें 16,500 देना होगा। पूरे पैसे देने के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। दया शंकर फिर बुधवार को बिजली दफ्तर पहुंचे और कनेक्शन प्रक्रिया पर सवाल उठाया और चुपके से बातचीत का वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस का दिख रहा असर, दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी

नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कुछ एक

इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे तापमान में कमी दर्ज की गई है। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस बताई जा रही है। इसका असर आज पूरे दिन रहने की उम्मीद है। वहीं इन बादलों के बीच से हल्की धूप भी निकली है। आसमान में बादल छाने से तापमान में कमी देखने को मिली। अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जाने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के मुताबिक सुबह बादल छाने के बाद दोपहर को हल्की बदली छाई रही। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं वातावरण में नमी की मात्रा 45 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 10 किमी प्रतिघंटा रहने की उम्मीद है। धूप और बदली का ये मौसम दिन भर रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी बादल छाने की उम्मीद है। इसके बाद मौसम साफ होगा। और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। फिलहाल नोएडा का मौसम सुहावना हो गया है। साथ ही कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है।

गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, 8 लोग झुलसे, तीन की हालत गंभीर

गाजियाबाद। गाजियाबाद के नंद ग्राम थाना इलाके के मेरठ रोड स्थित विकास नगर में कबाड़ के गोदाम में देर शाम आग लग गई और आग लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज लगभग 8:00 के करीब आग लगी और जैसे ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना मिली मौके पर तुरंत आग बुझाने के लिए गाड़ियां भेजी गई। लेकिन इससे पहले वहां पर कई लोग आज की चपेट में आ गए। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन तीन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। एसीपी आलोक दुबे ने बताया कि इस गोदाम में परफ्यूम की खाली बोतले से एलुमिनियम निकालने का काम चलता था। जिसके कारण यह भयंकर आग लगी। लगभग 1 घंटे बाद अग्निशमन की 6 गाड़ियों ने आग बुझा कर आग को बुझाया ।

भारत ने 2014 के बाद टीबी के खिलाफ नई सोच और दृष्टिकोण के साथ काम किया : प्रधानमंत्री मोदी

वाराणसी/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ जनभागीदारी को भारत की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने नई सोच और दृष्टिकोण के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वह अभूतपूर्व है। टीबी के खिलाफ इसे वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को यह जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' में अपने विचार रख रहे थे। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया है वह वास्तव में अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। उन्होंने कहा कि बीते नौ वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर जैसे- जनभागीदारी, पोषण के लिए विशेष अभियान, इलाज के लिए नई रणनीति, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान पर एकसाथ काम किया है।

प्रधानमंत्री ने टीबी समिट के अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरे लिए ये बहुत खुशी के बात है कि 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी शाश्वत धरा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है, तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है, टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानने के

भारतीय विचार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टि दे रहा है, एकीकृत समाधान दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने जी-20 समिट की भी थीम रखी है- 'एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य'! ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है।

टीबी रोगियों की पहचान और उपचार के लिए उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, हमने उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देशभर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है।

'नि-क्षय मित्र' पहल को लेकर उन्होंने कहा कि इससे टीबी की चुनौती से लड़ने में बहुत मदद मिली है। टीबी रोगियों के पोषण को बड़ी चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार 2018 में टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जनभागीदारी का बहुत बड़ा काम किया है। टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से %नि-क्षय मित्र% बनने का आह्वान किया था। इस अभियान के बाद करीब-करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने गोद लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टार्गेट वर्ष 2030 है लेकिन भारत वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर को टीबी मुक्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

कोरोना ने फिर दी दस्तक: पांच महीने बाद राजधानी में संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली में लंबे समय के बाद कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि जांच बढ़ने से संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में कोविड के एक्टिव केस 346 है। इनमें से 17 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं जबकि 212 मरीज ओम आइसोलेशन में हैं।

अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 11 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इनमें से ज्यादातर दूसरे बीमारी के मरीज भी शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब बुखार के सभी मामलों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।

जांच बढ़ाने के साथ अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ाने के साथ अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। दिल्ली में पिछले दो दिन (मंगलवार और बुधवार) से 80 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ

रहे हैं। संक्रमण दर भी 5 फीसदी रही। इसके अलावा मौसमी बीमारी के साथ इन्फ्लूएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि अभी समस्या गंभीर नहीं हैं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में उपसचिव (कोविड) ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में कोरोना व एच3एन2 के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से निपटने के लिए अस्पताल व प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहें। जरूरत के आधार पर दवाइयां व अन्य की व्यवस्था रखी जाए। साथ ही जांच का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने को कहा गया है।

दिल्ली भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पार्टी कार्यालय में स्वागत

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ऑफिस पहुंचे नवनियुक्त दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने मिठाई खिलाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने उन्हें पगड़ी पहनाई। समारोह में सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, पूर्व मेयर जय प्रकाश, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सचदेवा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है, उसका वह ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा से ही लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और हम लोग सभी पार्टी के साथ हर एक कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता के

साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सचदेवा ने कहा कि वह कभी अपने आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रुप में देखना पसंद करेंगे। वह भाजपा के एक छोटे से और सच्चे सिपाही हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है, उसको लेकर हम सब लगन और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला। 2024 में भी भाजपा की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बन कर आएंगे। सचदेवा ने बताया कि 2024 और 2025 को लेकर हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। एमसीडी के चुनाव में हमारी सीटें जरूर कम हुई, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा था इसलिए हम उसे हार नहीं मानते हैं।

'आप' का भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर आरोप, कहा- बीजेपी पार्षदों से वसूलते हैं एक-एक लाख रुपये प्रति माह

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज शुक्रवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर भाजपा पार्षदों से प्रति माह एक-एक लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस संबंध में सदन में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाने का प्रयास किया, जिसकी विधानसभा अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेनड्राइव मांगी।

आप और भाजपा विधायकों ने किया हंगामा

वहीं, विधानसभा में केंद्र सरकार और भाजपा सांसद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और घोर पूंजीवाद के संबंध में चर्चा के दौरान हंगामा हुआ भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस कारण हाउस आधा घंटा के लिए स्थगित किया गया।

दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अख्तियार किया

उधर, बिजली पर सब्सिडी देने संबंधी फाइल मंत्री के बजाय मुख्य

सचिव को भेजने के संबंध में दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अख्तियार किया। विधानसभा ने इसे सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस मामले को स्थाई समिति के पास भेजा। उपराज्यपाल सचिवालय से यह फाइल मुख्य सचिव के पास भेजी गई थी।

'एलजी को भेजी जा रही फाइल के कारण सरकार का काम हो रहा प्रभावित'

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास अधिकारियों द्वारा भेजी जा रही फाइल को लेकर दिल्ली विधानसभा में विधायकों ने विरोध किया। शालीमार से आप विधायक वंदना कुमारी ने कहा कि एलजी को भेजे जा रही फाइल के कारण दिल्ली सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं।

'उपराज्यपाल दिल्ली सरकार का काम रोक रहे'

दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई।

विधानसभा ने इसे सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस मामले को स्थाई समिति के पास भेजा। उपराज्यपाल सचिवालय से यह फाइल मुख्य सचिव के पास भेजी गई थी।

इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक राज्यपाल का धन्यवाद करने के बजाय उनकी निंदा करने में लग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार का काम रोक रहे हैं इसके अलावा वह दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हैं।

यूपी नगरीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुनवाई 27 मार्च तक टली

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब निकाय चुनाव और टलने की संभावना है। अब यूपी निकाय चुनाव के मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुका है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पहले ही पेश की जा चुकी है. 4 जनवरी को स्ट्र ने OBC आरक्षण कमेटी की रिपोर्ट तक चुनाव पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ही नगर विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। नगर निगम मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। सरकार का ऐसा मानना है कि अप्रैल से मई के दौरान चुनाव करा लिया जाए। ओबीसी आरक्षण से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग ने ढाई महीने से भी कम समय में सभी 75 जिलों का दौरा कर ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाए थे और पिछले हफ्ते सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। सरकार ने ये रिपोर्ट पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में करीब तीन महीने की देरी हो चुकी है। लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम जैसे नगर निगमों और 200 नगरपालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनका कामकाज प्रशासकों के हाथ में है। नगर निगम में नगर आयुक्त और नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी के हाथ में कमान है।

किरण रिजिजू बोले: राहुल ने लोकतंत्र का अपमान किया, लेकिन इसके लिए सभी गांधी सरनेम वालों को दोष नहीं दे सकते

नई दिल्ली। 'मोदी सरनेम' विवाद में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश की सियासत गर्म हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश बताया तो भाजपा ने भी पलटवार किया।

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी गांधी उपनाम वालों को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, सशस्त्र सेना और देश की संस्थानों का 'अपमान' किया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके राहुल पर निशाना साधा। लिखा, 'हम सभी गांधी उपनाम वालों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, हमारे सशस्त्र बलों और भारतीय संस्थानों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की

और पूरे ओबीसी समुदाय को अपमानित किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ कांग्रेस नेता इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।'इसके पहले गुरुवार को रिजिजू ने कहा था कि गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। राहुल की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी की किस्मत डूब रही है।

क्या है मामला, जिसमें राहुल को मिली सजा?

2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इसी मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है।

एनडीएमसी के चैयरमैन ने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष अमित यादव ने आज एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग स्कूल के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए फाउंडेशन स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, जिसे 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में लागू किया जा रहा है। नई नीति सभी सामाजिक वर्ग समूहों को उनके शिक्षा विकास के लिए शामिल करके हमारे देश में शिक्षा परिदृश्य को बदल देगी। उन्होंने आगे कहा कि नई नीति छात्रों द्वारा बहु-विषयक ज्ञान,

बुद्धि और जानकारी हासिल करने के लिए स्ट्रीम और उनके विषय समूहों के चुनाव में लचीलापन भी प्रदान करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईटी ज्ञान उपकरणों को शिक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जो तकनीकी सुधारों द्वारा हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।

यादव ने अटल आदर्श विद्यालयों और नवयुग स्कूलों के प्राथमिक स्कूली छात्रों द्वारा प्रदर्शित जी20 सदस्य देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी पर लगाई एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और उसका अवलोकन करते हुए दौरा किया। एनडीएमसी ने अपने सभी स्कूलों में जी20 जागरूकता के लिए जो पहल की है, उसमें स्कूली छात्रों ने जी20 विषय पर विभिन्न चार्ट, मॉडल और शिल्प बनाए हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ आंकी गई प्रदर्शन सामग्री को आज शिक्षको के लिये आयोजित कार्यशाला में प्रदर्शित भी किया गया।

दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए यूपीएससी ने 334 प्रिंसिपल नियुक्त

नई दिल्ली। यूपीएससी द्वारा चयनित 334 प्रिंसिपल में से दिल्ली सरकार स्कूलों के लगभग 100 शिक्षक और उपप्रधानाचार्य चयनित हुए और पुरुष व महिला दोनों श्रेणी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक काबिज रहे।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में इन प्रिंसिपलों से मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई दी। प्रिंसिपलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सभी 334 प्रिंसिपलों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आतिशी नवनियुक्त प्रिंसिपलों से कहा कि हमारे नवनियुक्त प्रिंसिपलों के पास शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों का लंबा अनुभव हैं और ये सभी इन स्कूलों की चुनौतियों और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। ये हमारे स्कूलों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करेंगे और स्कूल लीडर के रूप में कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रिंसिपल भर्ती की परीक्षा में पूरे देश के शिक्षकों ने भाग लिया और भर्ती किए गए कुल प्रिंसिपलों में से लगभग एक-तिहाई दिल्ली सरकार स्कूलों से हैं और शिक्षा को लेकर सरकार के विजन से अवगत हैं। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कहा कि अबतक आपने शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई और अब आप सभी स्कूल लीडर के रूप में दिल्ली की शिक्षा क्रांति बड़ी भूमिका निभायेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में इतनी बड़ी संख्या में प्रिंसिपलों की नियुक्ति होना ऐतिहासिक है।

उन्होंने साझा करते हुए कहा कि यूपीएसई ने आखिरी बार 58 प्रिंसिपल की नियुक्ति की थी और इसकी प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा 2011 में शुरू की गई थी और ये 2015 में पूरी हुई। यानि 58 पोस्ट को भरने में लगभग पांच साल का समय लगा था। लेकिन केजरीवाल सरकार के प्रयासों का नतीजा रहा कि 24 अप्रैल 2021 को 363 प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 थी। इसके उपरांत यूपीएससी द्वारा 17 जुलाई 2022 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस साल जनवरी के अंतिम व फरवरी के पहले सप्ताह में इंटरव्यू आयोजित किए गए और आज इसके नतीजे आ गये है। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 साल से भी कम समय में पूरी हो गई और नवनियुक्त प्रिंसिपलों की संख्या भी पिछली बार की तुलना में 7 गुणा अधिक है।

नोएडा में घर से भागी थी दो किशोरी,अब बालिका गृह का भी शीशा तोड़कर हुई फरार

नोएडा। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर-73 सर्फाबाद स्थित उदयन केयर बालिका गृह से दो किशोरियां संदिग्ध हालात में भाग गईं। वह द्वितीय तल स्थित शौचालय की खिड़की का शीशा तोड़कर भागीं ,इस संबंध में प्रबंधन ने थाने में केस दर्ज कराया है।

उदयन केयर एनजीओ के पदाधिकारी ने पुलिस को शिकायत दी है कि 16 वर्षीय और 14 वर्षीय दो नाबालिग किशोरी मंगलवार देर शाम बालिका गृह से फरार हो गईं। सुबह होने पर प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई। यहां पर द्वितीय तल पर शौचालय की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, तभी पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना

मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि दोनों किशोरी शौचालय से ही फरार हुईं।

पाक में ही होगा , एशिया कप , भारत के मैच अन्य स्थलों पर होंगे

दुबई (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के लिए अच्छी खबर है। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास ही रहेगी पर इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के मैच किसी अन्य स्थान पर खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए तैयार हो गये हैं हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, श्रीलंका और इंग्लैंड भी भारत के मैचों को आयोजित करने के लिए तैयार है। एशिया कप में छह टीमें भाग लेंगी। इसमें भारत और पाक एक ही समूह में रखे गये हैं।

इससे पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाक नहीं जाएगी। शाह एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने तब कहा था कि टूर्नामेंट तटस्थ स्थान पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा था, तटस्थ स्थान पर एशिया कप 2023 होगा। इसका पीसीबी ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद अब यह तय हुआ है कि एशिया कप पाक में ही होगा पर भारतीय टीम के मैच किसी अन्य स्थान पर होंगे। इससे पहले पाक बोर्ड का कहना रहा है कि भारतीय टीम पाक का दौरा करे। पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर भारत एशिया कप के लिए नहीं आता है और टूर्नामेंट को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पीसीबी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा। एसीसी के अध्यक्ष शाह ने पिछले साल दिसंबर में एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम जारी किया था पर उसमें एशिया कप के आयोजन स्थल का उल्लेख नहीं किया गया था। वहीं इस साल की शुरुआत में एसीसी की बैठक में आयोजन स्थल को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया था। बहरहाल अब यह मामला हल होता नजर आ रहा है।

भारत को मिला एक और कांस्य

-आईएसएसएफ़ वर्ल्ड कप में चीन 8 पदक के साथ शीर्ष पर

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल की मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ़ एक्सीलेंस में चल रही 8वीं आईएसएसएफ़ वर्ल्ड कप शूटिंग चेंपियनशिप में भारत के रूद्रांक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में 262.2 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। रूद्रांक्ष का इस वर्ल्ड कप में यह दूसरा पदक है। उन्होंने गुरूवार को मिक्स्ड इवेंट में अपने साथी नर्मदा राजू के साथ खेलते हुए कांस्य पदक जीता था। भारत के ही हृदय हज़ारिका 208.7 अंकों के साथ छठवें स्थान पर रहे। भारत एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है।

आईएसएसएफ़ वर्ल्ड कप में चाइना के खिलाड़ियों ने बाज़ी मारते हुए आज 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पुनः स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया। चायना के शेंग लिहाओ ने स्वर्ण और डूलिंशु ने रजत पदक जीता। चायना 5 स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। तीसरे स्थान पर अज़रबैजान, चौथे पर जर्मनी, पाँचवें पर हंगरी, छठवें पर अमेरिका और सातवें स्थान पर कज़ाकस्तिान है।

महिला 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भारत की रमीता ने 260.5 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। चायना की हुआंग यूटिंग ने 265.7 अंक के साथ स्वर्ण और यूएसए की मैरी टकर ने 261.2 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया।

आईपीएल से पहले धोनी को गेंदबाजी करते देखकर प्रशंसक हैरान हुए

चेन्नई (एजेंसी)। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी आजकल 31 मार्च से शुरु होने वाले आईपीएल की तैयारियों में लगे हैं। इसमें सीएसके को अपना पहला मैच गुजरात टाइटंस से खेलना है। पिछले साल सीएसके का प्रदर्शन खराब रहा था। ऐसे में इस बार धोनी अभ्यास में कोई कसर नहीं रखना चाहते। वह बल्लेबाजी के अलावा नेट्स में गेंदबाजी भी करते दिखे। ऐसा ही एक वीडियो धोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया हैं। इसमें वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते दिख रहे हैं।

सीएसके का यह वीडियो काफी अच्छा है। इसमें धोनी को गेंदबाजी करने के साथ ही छक्के लगाते हुए भी देखा जा सकता है। इसे देखकर लग रहा है कि धोनी स्वयं ही गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी गेंद पर वह छक्का भी लगा रहे हैं। इसके बाद वह शॉट को देखते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। धोनी के प्रशंसक उनके इस अंदाज को देखकर काफी उत्साहित हैं। प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह आईपीएल 2023 में भी अपने विरोधियों के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में खेलेंगे। इस बार आईपीएल अपने पुराने प्रारुप में खेला जाएगा। जबकि पिछले दो साल से कोरोना महामारी के कारण होम और अवे फॉर्मेट (घर ओर घर से बाहर) के मुकाबले नहीं खेले जा रहे थे। 16वें सीजन में अब पुराने प्रारुप की वापसी हो रही है। ऐसे में सभी टीमें अवे मैचों के अलावा अपने घरेलू मैदान पर भी मुकाबला खेलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि चेपॉक पर धोनी आईपीएल में अंतिम बार नजर आएंगे।

धोनी की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनका यह अंतिम आईपीएल माना जा रहा है क्योंकि इस लीग के बाद वह खेल से संन्यास ले सकते हैं। पिछले साल के आईपीएल में धोनी से जब उनके संन्यास को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह आईपीएल 2023 में खेलेंगे। ऐसे में अगर धोनी आईपीएल से संन्यास भी लेते हैं तो सीएसके के प्रशंस चाहेंगे कि वह अपने घरेलू मैदान पर अपनी टीम के लिए आखिरी मैच खेले।

अय्यर विश्व कप खेलने के लिए तैयार, अभी सर्जरी नहीं करायेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी पीठ की सर्जरी से इंकार करते हुए कहा है कि उनका ध्यान अभी विश्वकप खेलने पर है। अय्यर पीठ में चोट के कारण ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से भी बाहर हो गये हैं। इसके बाद हुई जांच में यह सामने आया है कि उनको सर्जरी की जरुरत है। सर्जरी के कारण उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रहना होगा। ऐसे में वह विश्वकप नहीं खल सकते। वहीं अय्यर ने अब कहा है कि वह विश्वकप खेलने के लिए तैयार हैं और अभी सर्जरी नहीं करायेंगे।

वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अय्यर का ध्यान आईपीएल से ज्यादा विश्वकप खेलने पर है। इसलिए वह सर्जरी के पक्ष में नहीं हैं। वह अगर सर्जरी कराते हैं तो वह कम से कम 6 से 7 महीने के लिए बाहर हो जाएंगे जिसके चलते वह विश्वकप नहीं खेल पाएंगे। इस वजह से अय्यर बिल्कुल भी खतरा मौल नहीं लेना चाहते। विश्वकप इस साल भारत में ही है। अक्टूबर-नवंबर में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। वहीं अय्यर के आईपीएल खेलने की तो इस मामले को लेकर अब तक किसी प्रकार की कोई पुष्टी नहीं की गई है। अय्यर आईपीएल का पहला चरण शायद ही खेलें। अय्यर ने भारत के लिए अब तक 49 टी20, 42 एकदिवसीय और 10 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। टी 20 में अय्यर ने 30.7 की औसत और 136 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1043 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक लगाये हैं। अय्यर ने एकदिवसीय में 46.6 की औसत से 2 शतक और 14 अर्धशतक की सहायता से 1631 रन बनाए हैं। वह एकदिवसीय विश्वकप के लिए नंबर चार बल्लेबाज के रुप में टीम प्रबंधन की पहली पसंद हैं।

शुभमन आने वाले समय में गुजरात टाइटंस के कप्तान बनेंगे : सोलंकी

मुम्बई (एजेंसी)। आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनमें नेतृत्व क्षमता भी है ओर वह भविष्य में गुजरात टीम के कप्तान बन सकते हैं। शुभमन ने भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद ही कम समय में ही सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले कुछ माह में पांच शतक लगाये हैं। जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय में दोहरा शतक लगाना भी शामिल है।

उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस को आईपीएल खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या का लगातार दूसरे सत्र में गुजरात टाइटंस की अगुवाई करना तय है पर टीम प्रबंधन शुभमन को भविष्य के कप्तान के रूप में आगे बढ़ाएगा। सोलंकी ने कहा, 'शुभमन के अंदर एक नेतृत्व के गुण हैं। वह अभी भी काफी जिम्मेदारी लेता है। मेरे हिसाब से यह जरुरी नहीं है कि कोई खिलाड़ी कप्तान होने पर ही अपनी भूमिका निभाए।

उन्होंने कहा, 'शुभमन ने पिछले साल भी अपने व्यवहार और खेल के प्रति अपने पेशेवर रवैए के कारण नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी। सोलंकी ने कहा, 'क्या मैं यह सोचता हूंकि शुभमन भविष्य का कप्तान होगा। हां, निश्चित तौर पर लेकिन इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वह बहुत परिपक्व है और काफी प्रतिभाशाली भी है।

स्विस ओपन में हारी सिंधु, सात्विक-चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची

बासेल । भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार के साथ ही बाहर हो गयी हैं। वहीं भारत के ही सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दूसरी वरीयता प्राप्त पुरुष जोड़ी जीत के साथ ही क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सिंधु को महिला एकल के दूसरे दौर में इंडोनेशिया की गैर वरीयता प्राप्त कुसुमा वारदानी ने तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 15-21, 21-12, 18-21 से हराया। वहीं पुरुष युगल में सात्विकसाईराज और चिराग की दूसरी वरीयता प्राप्त पुरुष जोड़ी ने ताइवान की फेंग चीह ली और फेंग जेन ली की जोड़ी को 12-21, 21-17, 28-26 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब इस भारतीय जोड़ी का सामना डेनमार्क के जेपी बे और लासे मोल्हेडे की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी एचएस प्रणय दूसरे दौर में फ्रांस के गैरवरीयता प्राप्त खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव के हाथों सीधे गेम में 8-21, 8-21 से हार के साथ ही बाहर हो गये। वहीं किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के चेउक यिउ ली ने 22-20, 21-17 से हराया।

जयसूर्या , अफरीदी और शाकिब के नाम है ये अहम रिकार्ड

नई दिल्ली । एकदिवसीय क्रिकेट में अब तक केवल तीन खिलाड़ियों के नाम ही 7000 रन और 300 विकेट लेने का एक रिकार्ड है। सबसे अहम बात यह है कि इस खास सूची में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है। एकदिवसीय प्रारूप में 7000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी सनथ जयसूर्या , पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन।

जयसूर्या ने अपनी टीम की ओर से एकदिवसीय प्रारूप में कुल 445 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान इस क्रिकेटर ने 433 पारियों में 32.13 की औसत से 13430 रन बनाये हैं। वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने अपनी टीम की ओर से 368 पारियों में 36.75 की औसत से 323 विकेट लिए हैं।

वहीं अफरीदी ने भी 7000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने की उपलब्धि अपने नाम हासिल की है। अफरीदी ने पाक की ओर से अपने क्रिकेट करियर में कुल 398 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 369 पारियों में 23.58 की औसत से 8064 रन भी बनाये हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 372 पारियों में 34.51 की औसत से 395 विकेट लिए हैं।

इसके अलावा बांग्लादेश के शाकिब ने एकदिवसीय प्रारूप में अबतक कुल 230 मुकाबले खेलकर 217 पारियों में 37.69 की औसत से 7086 रन बनाये हैं। इसके अलावा 225 पारियों में 28.94 की औसत से उन्होंने 301 विकेट लिए हैं।

आईपीएल के लिए विराट ने बदली हेयरस्टाइल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल से पहले ही नये लुक में नजर आये हैं। इस माह के अंत में शुरु हो रहे आईपीएल को देखते हुए ही खिलाड़ी अपने लुक में बदलाव करने लगे हैं। विराट भी आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के स्टार खिलाड़ी हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई सीरीज के अंतिम मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया था। अभी 31 मार्च से शुरु हो रहे आईपीएल की तैयारियों में खिलाड़ी लगे हैं। आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी नजर आयेंगे। एकदिवसीय सीरीज के बाद सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी अलग-अलग हेयर स्टाइल रखते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब नया आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट ने भी अपने लुक में बदलाव किया है।

विराट ने नई हेयरस्टाइल बनवायी है। विराट ने सोशल मीडिया के सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें कोहली अपने नए हेयर कट में नजर आ रहे हैं। वहीं उस तस्वीर में उनके हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम भी नजर आ रहे हैं। हाकिम काफी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं। विराट का यह नया लुक उन पर काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कोहली ने आलिम हाकिम को अपनी स्टोरी में जादूगर भी बताया है। उन्होंने हाकिम को लेकर लिखा शुक्रिया जादूगर। ऐसे में अब विराट कोहली की यह स्टोरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। विराट अपना नया हेयर कट कराने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इंडियंस स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स में भी दिखे। कोहली ने अवॉर्ड समारोह के लिए काला सूट पहना था जबकि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर्पल रंग के परिधानों में नजर आ रहीं थी। अनुष्का ने इस इवेंट की कुछ तस्वीरें विराट के साथ इंस्टाग्राम पर साझा भी की हैं। विराट का लक्ष्य आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर आगामी विश्वकप को देखते हुए अपनी लय और बेहतर बनाना रहेगा।

रोनाल्डो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले फुटबॉलर बने, टीम को दिलाई जीत

लंदन । क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन ने 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालीफाइंग मैचों में गुरुवार को नए रिकॉर्ड बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। पुर्तगाल के रोनाल्डो पहले ही पुरुष फुटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और अब उनके नाम पर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने का नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। रोनाल्डो ने यह रिकॉर्ड लिचेंस्टीन के खिलाफ पुर्तगाल की 4-0 से जीत के दौरान बनाया। यह उनका 197वां अंतरराष्ट्रीय मैच था। इससे पहले रोनाल्डो और कुवैत के बादेर अल मुतावा के नाम पर 196 मैच खेलने का संयुक्त रिकॉर्ड दर्ज था। रोनाल्डो ने इस मैच में दूसरे हाफ में पेनल्टी को गोल में बदलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कुल गोल की संख्या को 120 पर भी पहुंचाया। इस बीच केन इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड की इटली पर 2-1 से जीत के दौरान पहले हाफ में पेनल्टी को गोल में बदला। यह उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 54वां बोल था जो कि वायने रूनी से एक गोल अधिक है। यूरो 2024 का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा जिसके क्वालीफाइंग मैचों की शुरुआत विश्वकप समाप्त होने की तीन महीने बाद हुई है।

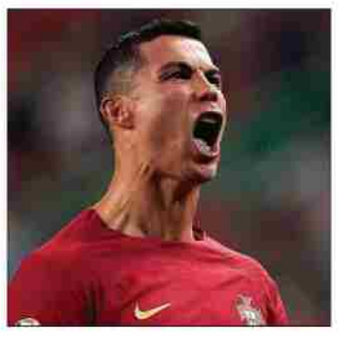

सूर्यकुमार की जगह सैमसन को शामिल करने की मांग उठी

मुम्बई (एजेंसी)। आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों में असफल होने के बाद उनकी जगह एकदिवसीय विश्वकप के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अवसर देने की मांग तेज हो गयी है। वहीं इससे पहले कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि उन्होंने विश्वकप के लिए टीम तय कर ली है और सूर्यकुमार को इस टीम में रखा जाएगा। वहीं अब सैमसन के प्रशंसकों का मानना है कि यह सही नहीं है। उनका कहना है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही टीम में जगह मिलनी चाहिये। प्रशंसकों के अनुसार एक खिलाड़ी को लगातार विफल होने के बाद भी अवसर देना सही नहीं है। यह उसी प्रकार है जैसे लोकेश राहुल को टेस्ट में लगातार विफल होने के बाद भी अपने को साबित करने के लिए अवसर मिलते रहे हैं। वहीं सैमसन जैसे खिलाड़ी को शानदार रिकॉर्ड के बावजूद वो अवसर नहीं मिल पा रहें है जिससे वो कम से कम विश्वकप के लिए अपना दावा तक कर सकें। वहीं सूर्या सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में एक रन भी नहीं बना पाये हैं। इस बल्लेबाज ने 7 मैच की 6 पारियों में 8 की औसत 49 रन बनाए हैं। इसमें 31 रन उनका सबसे अधिक स्कोर है। इसके बाद भी द्रविड़ और टीम प्रबंधन उनके बचाव में नजर आया द्रविड़ ने ये भी कहा, हमारे 15 से 16 खिलाड़ि?यों में कई संयोजन हैं जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। एकदिवसीय विश्व कप एक बड़ा टूर्नामेंट है। भारत के कई शहरों में खेला जाएगा और जहां 9 अलग हालात हैं। ऐसे में आप अपनी टीम में लचीलापन चाहते हैं, जिसमें आप कई बार चार तेज गेंदबाज खिला सकें... कई बार तीन स्पिनर। इसी लचीलेपन को पाने के लिए हम कई विकल्प की ओर देख रहे हैं। इस बात से खुश हूं कि हमने सभी परिस्थतियों को कवर कर लिया है। हैरानी की बात है कि द्रविड़ लचीलेपन और विकल्प जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो अपने बयान में कर रहे हैं लेकिन कई खिलाड़ियों के चयन की संभावनाओं को लेकर ये बात गले उतरते नहीं दिखती है।

महिला एथलेटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगी ट्रांसजेंडर महिलाएं : सेबेस्टियन

नई दिल्ली । विश्व एथलेटिक्स संघ ने कहा है कि ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स में भाग नहीं ले सकती हैं। विश्व थलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने अपने एक बयान में कहा कि महिलाओं के मुकाबलों में ट्रांसजेंडर महिला एथलीट भाग नहीं ले सकेंगी। सेबेस्टियन ने कहा कि किसी भी ट्रांसजेंडर एथलीट को 31 मार्च से महिला विश्व रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार इस टूर्नामेंट में भाग लेने को लेकर टेस्टोस्टेरोन का आधार समाप्त हो गया है। ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड फेडरेशन की एक बैठक के बाद सेबेस्टियन ने कहा कि विश्व एथलेटिक्स ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के मामले में 40 राष्ट्रीय महासंघों, अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति और ट्रांस समूहों सहित हितधारकों के साथ विचार किया था। इस बैठक में अधिकतर सदस्यों ने कहा कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि महिला ट्रांसजेंडर कभी पुरुष थे, ऐसे में उन्हें महिला एथलीटों से अधिक मजबूत माना जाता है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विकास की निगरानी के लिए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कार्य समूह बनाया जाएगा। सेबेस्टियन ने कहा, हम हमेशा के लिए उन्हें इंकार नहीं कर रहे हैं। हम इसमें शारीरिक प्रदर्शन और पुरुष लाभ को लेकर आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक आधार पर फैसला कर सकते हैं। जैसे ही इस बात का सबूत मिलेगा कि ट्रांसजेंडर को शारीरिक रूप से फायदा नहीं मिल रहा है तो हम अपने फैसला की समीक्षा करेंगे। हमारा मानना है कि एथलेटिक्स में महिला वर्ग की अखंडता सर्वोपरि है। वहीं इससे पहले के नियमों के तहत विश्व एथलेटिक्स में ट्रांसजेंडर महिलाओं को अपने रक्त टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को अधिकतम 5 एनएमओएल/एल तक कम करने और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने से पहले 12 महीने की अवधि के लिए लगातार इस सीमा के अंदर होना चाहिये था।

अब विश्वकप की तैयारी के लिए भारतीय टीम के पास हैं केवल 12 एकदिवसीय मैच

मुम्बई (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अक्टूबर-नवंबर में विश्व कप होना है और टीम के पास बेहद कम समय है जिसमें उसे अपनी लय पूरी करनी है। टीम के कई अहम खिलाड़ी चोटिल हैं और उनका खेलना संदिग्ध बना हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय टीम अपनी घरेलू पिचों पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और स्पिनर एडम जंपा के सामने बेबस नजर आयी। उससे उसकी विश्वकप तैयारियों की भी पोल खुल गयी है।

श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को मौका दिया गया। मगर वो असफल रहे। अब खिताड़ी आईपीएल खेलेंगे पर इस दौरान प्रबंधन को विश्वकप की तैयारियों को भी ध्यान में रखना होगा।

अब भारतीय टीम के पास विश्व कप की तैयारी को लेकर केवल 12 एकदिवसीय मैच बचे हैं। इसमें भी 6 मैच द्विपक्षीय सीरीज के तहत खेले जाएंगे जबकि फाइनल सहित 6 मैच उसे एशिया कप में खेलने हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास तैयारी का भी ज्यादा समय नहीं है।

टीम प्रबंधन को इन्हीं बाकी बचे मैचों में अपने अच्छे अंतिम-11 संयोजन को तलाशना होगा। मध्य क्रम में भी अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना होगा। इसके अलावा बेहतर गेंदबाज भी रखने होंगे। कुल मिलाकर इन बाकी बचे मैचों में ही टीम इंडिया को अपने प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना होगा।

आईपीएल के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलनी है। आईपीएल के ठीक बाद भारतीय टीम इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेलेगी। उसके बाद टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट, 3 एकदिवसीय और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद भारतीय टीम को एशिया कप भी खेलना है। एकदिवसीय प्रारुप में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान के ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम 2 मैच खेलेगी। यदि क्वालिफाई करती है, तो सेमीफाइनल में राउंड रॉबिन के तहत टीम इंडिया को 3 मैच खेलने होंगे. फाइनल में पहुंचने पर भारतीय टीम का यह टूर्नामेंट में छठा मुकाबला होगा। एशिया कप के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलेगी

एल्पाइन स्पोर्टिंग ने जीती पुरुष 'ए' डिवीजन प्रतियोगिता

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुरुष ए डिवीजन टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। आज रंगपो क्रिकेट ग्राउंड में खेले गये फाइनल मैच में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पाकिम इलेवन और एल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेले गये इस मैच में एल्पाइन स्पोर्टिंग ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीती।

आज फाइनल मैच के दौरान राज्य के खेल व युवा मामलों के मंत्री कुंगा नीमा लेख्चा, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्री बीएस पंत, महिला व बाल विकास मंत्री संजीत खरेल, शहरी विकास मंत्री एलबी दास, सड़क व सेतु मंत्री साम्दुप लेप्चा के अलावा खेल व युवा मामलों के सचिव राजू बस्नेत, पाकिम डीसी ताशी चोफेल, एसपी कर्मा ग्याम्त्सो, सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मेनला एथेन्पा और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार, 5 मार्च से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पाकिम इलेवन और एल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब फाइनल में पहुंचीं थीं। फाइनल के बाद उल्लेखनीय खिलाडियों को पुरस्कृत किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच फिनाले अल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब के आशीष थापा को चुना गया।

वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंकुर मलिक, जेबीसीसी 'ए' जोरथांग, पाकिम इलेवन के प्राणेश छेत्री बेस्ट बैट्समैन ऑफ द मैच, सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब एल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब के आशीष थापा और सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर का खिताब अल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब के अरुण छेत्री को दिया गया। फाइनल के सर्वाधिक स्कोरर पाकिम इलेवन के ओम सैनी रहे।

फरवरी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिलेटलिक प्रतियोगिता में उत्तर बंगाल और सिक्किम क्षेत्र से भाग लेकर मेडल जीतने वाले डाक टिकट संग्रकर्ता उदय मनि प्रधान, विवेक योंजन और रोशन प्रसाद को शुक्रवार को सिलीगुड़ी फिलाटेलीक ब्यूरो में सम्मानित करते सिक्किम तथा उत्तर बंगाल के पोस्टमास्टर जनरल कर्नल अखिलेश कुमार पाण्डे। इस अवसर में सिलीगुडी फिलाटेलीक ब्यूरो के नएं काउन्टर का भी सिलीगुड़ी प्रधान डाकघर में उन्होंने उद्घाटन किया।

'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से आधुनिक विश्व को मिल रहा एकीकृत दृष्टिकोण व समाधान : पीएम मोदी

वाराणसी, 24 मार्च (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वन वर्ड टीबी समिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।

उन्होंने कहा कि भारत हर देश के साथ टीबी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बटन दबाकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला, वाराणसी शाखा का शिलान्यास किया। फिर अपना संबोधन शुरू किया।

उन्होंने कहा कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब 'वसुधैव कुटुंबकम की भावना में झलकता है और यह प्राचीन विचार आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टिकोण तथा समाधान दे रहा है।

अपने संबोधन की शुरुआत 'हर-हर महादेव' के जयघोष से करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच तथा दृष्टिकोण के साथ तपेदिक (टीबी) के खिलाफ काम करना शुरू किया वह वाकई अभूतपूर्व है।

मोदी ने कहा, ''नौ वर्षों में टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है जैसे जनभागीदारी, पोषण के लिए विशेष अभियान, इलाज के लिए नई रणनीति, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले खेलो इंडिया और योग जैसे अभियान।''

इसके पहले प्रधानमंत्री ने टीबी रोकथाम उपचार (टीपीटी) की आधिकारिक शुरुआत के रूप में टीबी मुक्त पंचायत समेत अनेक परियोजनाओं और क्षयरोग के लिए एक परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की शुरूआत की। उन्होंने इस मौके पर भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 भी जारी की।

मोदी ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड हाई कंटेनमेंट प्रयोगशाला की वाराणसी शाखा की आधारशिला भी रखी और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट, वाराणसी का अनावरण किया।

इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मोदी का स्वागत किया। इस आयोजन में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की अधिशासी निदेशक डॉ लुसिका दितिउ ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में 2025 तक क्षय रोग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने नारा दिया ''टीबी हारेगा-इंडिया जीतेगा, टीबी हारेगी-दुनिया जीतेगी।''

इससे पहले, शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया।

ड्रग्स के लिए हमारे समुद्री मार्गों का इस्तेमाल नहीं होने दे सकते : अमित शाह

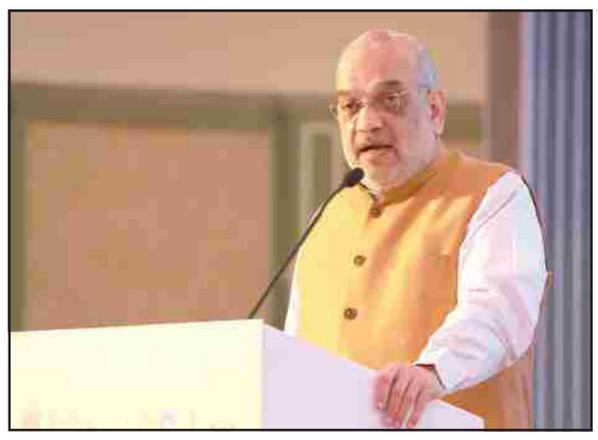

बेंगलुरु, 24 मार्च (एजेन्सी)। नशीले पदार्थों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने यहां 'ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' शीर्षक से दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे समुद्री मार्गों को नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नौसेना और कुछ राज्यों की पुलिस को दखल देना होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच यात्रा करने वाले कई जहाजों में अक्सर मादक पदार्थ लदे होते हैं, जिनकी आपूर्ति श्रीलंका से अमेरिका को की जाती है। शाह ने जोर देकर कहा, इसे रोकना होगा, अन्यथा हम ड्रग्स को भारत में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते।

शाह ने कहा, 'हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। अगर नशीला पदार्थ, चाहे वह कोई भी बेच रहा हो, नष्ट नहीं होता है, तो उसे यहां बेचा जाएगा। हमारा मकसद दुनिया में कहीं भी ड्रग्स बेचने वालों को कमजोर करना होना चाहिए।' गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का राज्यों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैं सभी राज्यों और संबंधित विभागों से ड्रग्स, अन्य नशीले पदार्थ, दोषियों और लत के खिलाफ अभियान में एकजुट होने की अपील करता हूं। समय पर प्रतिक्रिया समय की मांग है। शाह ने कहा कि हालांकि नशीले पदार्थों के खतरे से निपटना गृह मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है, राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा और संस्कृति जैसे अन्य विभागों को इस खतरे को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिलाना चाहिए।

शाह ने राज्यों को जब्त दवाओं को लेकर सावधान रहने की भी चेतावनी दी क्योंकि गृह मंत्रालय को सूचना मिल रही है कि कुछ जगहों पर पुलिस की हिरासत से मादक पदार्थ की चोरी हो रही है। इस अवसर पर, शाह ने 1,235 करोड़ रुपये मूल्य की 9,298 किलोग्राम जब्त दवाओं को नष्ट करने के लिए हरी झंडी दे दी।

नड्डा पर खड़गे का पलटवार, कहा- पहले चोरी में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि वह ललित मोदी और नीरव मोदी का बचाव तथा जातिगत राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं जो शर्मनाक है।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए यह भी कह कि मनु की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग अन्य पिछड़गे वर्गों के कल्याण की बात कर रहे हैं।

खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, कौन इस देश के पैसे लेकर भाग गए और कौन एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) और एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के पैसे लेकर अमीर बने, ढाई साल में 12 लाख करोड़ रुपये किसने कमाया? इसका जवाब दीजिए। मुद्दे को भटकाने का प्रयास मत करिये।

उन्होंने कहा, कांग्रेस ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है और उनके कल्याण के लिए काम किया। जो लोग मनु की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वे क्या ओबीसी की बात करते हैं?

खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) से भाग नहीं सकती ! पंजाब नेशनल बैंक व जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी भागे ! ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा, फिर उनका अपमान कैसे हुआ? स्टेट बैंक और एलआईसी को नुक़सान आपके परम मित्र ने पहुंचाया !

खड़गे ने कहा, एक तो चोरी में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग ! शर्मनाक!

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, जेपी नड्डा हमेशा की तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। वे ऐसा करके नीरव मोदी और ललित मोदी का बचाव कर रहे हैं। इस सच को सामने आना ही था और अब आ गया है।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद नड्डा जी। अब कृपया अडाणी पर भी थोड़ी ईमानदारी दिखाएं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ठोस राजनीतिक विमर्श लोकतंत्र का सार होता है। लोकतांत्रिक विपक्ष की प्रमुख आवाज को खामोश करने के लिए कानून का उपयोग ऐसे नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नड्डा ने सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शुक्रवार को निशाना साधा और कहा कि उनका अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज का अपमान किया और उन्हें 'चोर' कहा।

उन्होंने कहा, 'समाज और अदालत द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने (राहुल ने) नज़रअंदाज़ किया और ओबीसी समाज की भावना को लगातार ठेस पहुंचाई।'

राहुल को उनके कृत्य की सजा मिली है : पह्लाद जोशी

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले को अदालत के आदेश का परिणाम बताया और इसे उचित ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें उनके कृत्य की सजा मिली है।

गांधी की सदस्यता समाप्त होने संबंधी अधिसूचना के सार्वजनिक होने के कुछ देर बाद ही संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होता है। राहुल गांधी गाली दे रहे थे। वह कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे। ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे... उन्हें इस कृत्य की सजा मिली है।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान यादव के साथ केंद्रीय कानून व विधि राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी भी मौजूद थे।

यादव ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें अवसर भी दिया गया, ताकि वह अपना पक्ष रख सकें। उन्होंने कहा, लेकिन जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं...अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है।

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के संदर्भ में जो निर्णय दिया है, उसके अनुसार कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों के मामले में कार्रवाई हुई है।

उन्होंने कहा, मेरा अब भी मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पर... अपशब्द कहने पर, कांग्रेस को भी राहुल गांधी के साथ माफी मांगनी चाहिए।

ज्ञात हो कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने अयोग्यता को वैध करार दिया और कहा कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा के एक विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह फैसला कानूनी है और आरोप लगाया कि कांग्रेस न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा, यह एक कानूनी फैसला है और राजनीतिक दल द्वारा लिया गया फैसला नहीं। यह एक अदालत द्वारा लिया गया फैसला है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

कौशांबी से भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि राहुल ने पूरे समुदाय का अपमान किया है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह अदालत का फैसला है और जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय को बदनाम किया, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह अयोग्यता एक अच्छा संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।

विश्व तपेदिक दिवस मना

टीबी उन्मूलन में सामूहिक प्रयास पर बल

अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 24 मार्च । 'हां! हम टीबी खत्म कर सकते हैं' थीम पर आज नामची जिला अस्पताल सभागार में जिला तपेदिक केंद्र द्वारा विश्व तपेदिक (टीबी) दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नामची नगर परिषद अध्यक्ष गणेश राई के अलावा जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीसी शर्मा, जिला चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसएन अधिकारी, जिला तपेदिक रोग अधिकारी डॉ. अंजू राई, डीआरसीएचओ डॉ. जुनिता योन्जन की उपस्थित थी। उनके साथ नामची सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विभिन्न कर्मचारी और छात्र भी यहां मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने गणेश राई ने टीबी के सम्पूर्ण निदान में इसकी चिकित्सा, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के संदर्भ में व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इसके निदान में तत्काल प्रतिक्रिया उचित है और कुशल उपचार से इसे कम किया जा सकता है। वहीं उन्होंने खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी से जुड़े कलंक और भेदभाव को रेखांकित किया और उपस्थित लोगों विशेष रूप से युवाओं से टीबी की अवधारणा को समझने तथा कलंक व भेदभाव मुक्त माहौल में उचित उपचार की वकालत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में सिक्किम सभी सम्बंधितों के सम्मिलित प्रयासों से तपेदिक उन्मूलन हेतु प्रयास करेगा।

वहीं नामची सीएमओ डॉ. शर्मा ने तपेदिक बीमारी के विभिन्न पहलुओं, इसके लक्षणों और इलाज के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने टीबी में 20 प्रतिशत की कमी आने को इससे निपटने में एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए नामची जिला अस्पताल में एक सुसज्जित टीबी केंद्र होने की जानकारी दी। टीबी केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रतीक रसाइली ने संक्षेप में तपेदिक के कारणों, लक्षणों और बचाव के बारे में बताते हुए इसके मरीजों की प्रभावी चिकित्सा हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित योजनाओं के माध्यम से चिकित्सा, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने की बात कही।

कार्यक्रम में तपेदिक पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

डियर साप्ताहिक लॉटरी हूगली निवासी ने ₹1 करोड़ जीते

हूगली, पश्चिम बंगाल के श्री संजीत मंडल ने **15.02.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **45E 54252** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। ''जब मुझे यह पता चला कि मैंने डियर लॉटरी से पुरस्कार राशि के एक करोड़ रुपए जीत लिए हैं, तो मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार से आया हूं और अपने पास इतनी भारी-भरकम रकम होने की कोई गुंजाईश नहीं थी। डियर लॉटरी ने मुझे एक करोड़पति बना कर एक नई जिंदगी दे दी है। मैं डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज को धन्यवाद देना चाहता हूं।'' विजेता ने कहा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com